राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 2 ■ अंक 7 ■ अक्टूबर 2018 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 32

शहरी नक्सल

भारत के विरुद्ध अपवित्र गठजोड़

ममता की निर्ममता, छात्रों को शिक्षक के बदले मिली मौत 12

मिशन साहसी : 'निर्भर नहीं निडर' 22

MAHARAJA HARI SINGH THWARTED BRITISH CONSPIRACY: ACCEDED J&K TO INDIA 28

छात्रसंघ चुनाव

दिल्ली विश्वविद्यालय में जीत के बाद स्वामी विवेकानंद प्रतिमा के पास खुशी का इजहार करते नवनिर्वाचित छात्रसंघ के पदाधिकारी, साथ में हैं अभाविप, दिल्ली के प्रांत मंत्री भरत खटाना

देहरादून के डीएवी कॉलेज में लगातार 12 वीं जीत पर विजय जुलूस निकालते अभाविप कार्यकर्ता, साथ में हैं नवनिर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारी एवं अभाविप पदाधिकारी

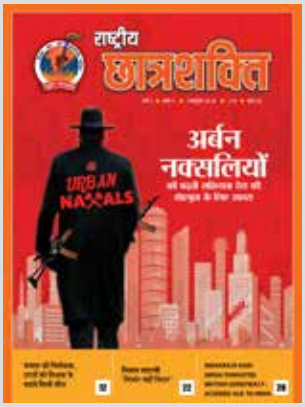

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 2, अंक 7
अक्टूबर, 2018

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

इस अंक में

05 **शहरी नक्सलः भारत के विरुद्ध अपवित्र गठजोड़**
सर्वहारा' की लडाई लड़ने का दावा करने वाले माओवादियों की विशेष प्रकार की रणनीति है। देश में निर्वाचित हुई...

संपादकीय	04
नक्सलियों ने जिल्लत के सिवा क्या दिया आदिवासियों को	09
ममता की निर्ममता, छात्रों को शिक्षक के बदले मिली मौत	12
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अभाविप ने लहराया जीत का परचम	15
उत्तराखंड के छात्रसंघ चुनाव में अभाविप का डंका	17
दरकते कुनबे को बचाने के लिए हिंसा का सहारा	18
दरकते कुनबे को बचाने की आखिरी कोशिश हिंसा	18
महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अभाविप ने निकाली 1,111 फीट की तिरंगा यात्रा	21
मिशन साहसी : 'निर्भर नहीं निडर'	22
अभाविप की मांगों के आगे झुका लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन	23
अभाविप के संघर्षों का परिणाम है, हरियाणा में छात्रसंघ चुनाव : विक्रांत खंडेलवाल	24
महेन्द्रगढ़ सामूहिक दुष्कर्म घटना, सभ्य समाज पर कलंक : आशीष चौहान	25
राफ़ेल, राजनीति व राष्ट्र सुरक्षा	26
MAHARAJA HARI SINGH THWARTED BRITISH CONSPIRACY: ACCEDED J&K TO INDIA	28

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

जब खुफिया जांच एजेंसी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जांच करने चली थी तो उसे पता नहीं था कि तार उन लोगों से जुड़े मिलेंगे जो जंगल में नहीं, शहरों में रहते हैं, शान की जिंदगी जीते हैं और भारत विरोधी हर घटना में आरोपियों के पक्ष में खड़े दिखते हैं।

प्रक्रिया तो यही है कि जिस पर आरोप लगे हों उसे गिरफ्तार किया जाय और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाय। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये जाने पर उसे जेल भेज दिया जाय ताकि वह सबूतों से छेड़-छाड़ न कर सके, गवाहों को न धमका सके और कथित षड्यंत्र को अंजाम देने में सफल न हो सके। इसी प्रक्रिया के चलते मालेगांव, गुजरात दंगों और ऐसी ही तमाम घटनाओं के आरोपी बरसों से जेल में हैं, हालांकि उन पर आज तक आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं। लेकिन जब बारी शहरी नक्सल समर्थकों की आयी तो देश में एक तूफान सा खड़ा हो गया। न्यायपालिका ने भी सहृदयता बरतते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा कर उन्हें घर में ही नजरबंद करने के आदेश दिये।

भारतीय न्यायिक इतिहास में भी शायद यह अनूठा मामला होगा। बड़े-बड़े राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी भी बिना आरोप सिद्ध हुए ही तिहाड़ में अपने दिन बिता रहे हैं। यह इन शहरी नक्सलियों की सफलता है कि वे मानवाधिकारवादी, सिविल सोसाइटी, आरटीआई एक्टिविस्ट जैसे मुखौटे लगाये शहरों में सक्रिय रहे और ऐसी मजबूत और उजली छवि गढ़ी कि समाज का बड़ा वर्ग उन्हें रॉबिनहुड जैसा मानने लगा।

जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दस्तावेज अर्बन पर्सपेक्टिव पढ़ा है वे जानते हैं कि यह एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। इस दस्तावेज में माओ को उद्धृत कर कहा गया है कि "क्रांति का अंतिम उद्देश्य शहरों पर कब्जा करना है, जो शत्रु का मूल आधार हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारा काम शहरों में पर्याप्त मात्रा में नही हो जाता है।" दस्ता वेज में कहा गया है कि शहरी इलाकों में पार्टी के कार्य में एक प्रमुख कार्य शत्रु के शिविर में घुसपैठ है। सामरिक बलों के साथ-साथ अर्ध सामरिक बल, पुलिस तथा प्रशासनिक मशीनरी के उच्च स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों में घुसपैठ अत्यंत जरुरी है। इन लोगों से शत्रु की गतिविधियों की गुप्त सूचना प्राप्त करना, क्रांति के लिए समर्थन जुटाना तथा शत्रु शिविर से आवश्यक होने पर विद्रोह कराना आदि कार्य किया जाएगा।

नक्सलियों की यह घोषित रणनीति लिखित रूप में उपलब्ध होते हुए भी यदि कोई समाज, व्यवस्था या देश अपने उनींदेपन से बाहर नहीं आता तो निश्चित ही चिंताजनक है। भारत में यह अपवित्र गठजोड़ वामपंथी आंदोलन का अतिक्रमण कर अन्य देशविघातक शक्तियों के साथ ताल-मेल बिठा चुका है जिसे बाहरी शक्तियों का भी समर्थन हासिल है। भारत को जागना होगा और घर में छिपे गद्दारों को बेनकाब करना होगा।

यह माह शारदीय नवरात्र तथा विजयादशमी को संजोये हैं। शक्तिरूपेण माँ की आराधना और धर्म की विजय के आख्यान को मन में तो धारण करें ही, कर्म में भी उतार सकें तो अपना कर्तव्य निर्वहन पूरा होगा।

हार्दिक शुभकामना सहित,

संपादक

अर्बन नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता देश की संप्रभुता के लिए खतरा

| समन्वय नंद |

'सर्वहारा' की लडाई लड़ने का दावा करने वाले माओवादियों की विशेष प्रकार की रणनीति है। देश में निर्वाचित हुई सरकारों को उखाड फेंकने उनका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर कार्य करने वाले माओवादी एक तरफ ग्रामीणों में पहले 'स्टेट' के खिलाफ बरगलाते हैं और उसके बाद उनके समर्थक बनाते हैं। धीरे-धीरे उन्ही समर्थकों में से लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार करते हैं। उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके पश्चात वे इन्हें हमले में झौंकते हैं। इनका एक निश्चित प्रक्रिया होता है। आम तौर पर माओवादियों के इस रणनीति के बारे में सभी को जानकारी है।

माओवादियों का यह वर्ग अपने रणनीति के अनुसार जंगलों में छुप - छुप कर छापामार लडाई लडता है। लेकिन माओवादियों का यह दूसरा वर्ग जंगलों में छुप कर नहीं रहता है। वे शहरों में रहता है और अपने आप को बुद्धिजीवी बता कर इस तथाकथित क्रांति में अपना योगदान देता है।

नक्सली या माओवादियों की सहायता करने के आरोप में डा. विनायक सेन, कोबाड घांडी व दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक साईं बाबा की गिरफ्तारी हुई थी। विनायक सेन व साई बाबा को तो न्यायालय ने दोषी भी करार दिया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या करने की साजिश रचने के आरोप में पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनमें गौतम नौवलखा, सुधा भारद्वाज, वी. गोंजाल्वेस, अरुण परेरा व वारवरा राव हैं। इन घटनाओं के सामने आने के बाद शहरी इलाकों में नक्सलवादियों का काम उनके काम करने के तरीके, उनका उद्देश्य, योजना व लक्ष्य के बारे चर्चा धीरे - धीरे बढ़ रही है। इसके बाद ही अर्बन नक्सल शब्द का अधिक प्रचलन शुरु हो गया है। अन्यथा इससे पहले इस तरह के लोगों को मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील,

पीड़ितों के लिए लडाई लड़ने वाला आदि बताया जाता रहा था और ये लोग इसकी चोला पहने रहते हैं।

माओ का कहना था "यह पूरी तरह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम व सशस्त्र संघर्ष हमारे लिए प्राथमिक भूमिका लेगी शहरों में काम हमारे लिए प्राथमिक न होते हुए दूसरी भूमिका लेगी, लेकिन दोनों पूरक के रुप में काम करेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र में काम पर प्राथमिक ध्यान देना होगा साध ही हमें शहरो के काम पर ध्यान देना होगा। शहरी क्रांतिकारी आंदोलन के बिना चल रह जन संघर्ष को दिक्कत आयेगी। शहरी लोगों के भागीदारी के बिना इसमें समस्या दिखाई देगी।"

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का एक दस्तावेज 'अर्बन पर्सपेक्टिव' के नाम पर उपलब्ध है जिसमें शहरी क्षेत्रों में नक्सलवादियों का काम कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में उल्लेख होने के साथ साथ काम करने का तरीका क्या हो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिक्कतें क्या है तथा उन्हें कैसे दूर किया जाए इसका संपूर्ण विवरण है।

इस दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद उनके काम करने के तरीकों के बारे में एक स्पष्ट चित्र मिलता है।

इस दस्तावेज में माओ को उद्धृत कर कहा गया है कि "क्रांति का अंतिम उद्देश्य शहरों पर कब्जा करना है, जो शत्रु का मूल आधार है और इस उद्देश्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारा काम शहरों में पर्याप्त मात्रा में नही हो जाता है।"

इस दस्तावेज के अनुसार भारत का 27.8 प्रतिशत आबादी कस्बों व शहरों में रहता है। चीन में जब क्रांति हुई थी तब वहां 10 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे। यानी भारत में क्रांति के लिए शहरी इलाकों की भूमिका चीन से अधिक होगी।

दस्तावेज के अनुसार " एक शक्तिशाली शहरी क्रांतिकारी आंदोलन के बिना इस लगातार जारी जनयुद्ध में बाधाएं आ रही हैं, साथ ही शहरी लोगों के भागीदारी के बिना देशव्यापी विजय संभव नहीं है।"

> किसानों व शहरी इलाके में कार्य का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामरिक कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में सामरिक कार्य करने का कार्य मूल रुप से पीजीए व पीएलए का है लेकिन ग्रामीण इलाकों में कैडरों को भेजना आदि काम शहरी आंदोलन का है। इसके अलावा शत्रु के रैंक में घूसपैठ व लाजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना भी इसमें शामिल है। सभी वर्गों को संगठित व प्रेरित कर व्यापक जनक्रांति की तैयारी करना व अंत में सशस्त्र क्रांति को अंजाम देना जैसाकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके सहयोगी नक्सलवादी चला रहे हैं। इसमें स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि पहला उद्देश्य यानी लोगों को संगठित व प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बिना शेष दो उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है।

अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक दृष्टिकोण

इस दस्तावेज में दीर्घकालिक दृष्टिकोण (लांग टर्म अप्रोच) का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि शहरी इलाकों में शत्रु काफी शक्तिशाली है तथा पार्टी का काम कमजोर होने के कारण शहरी इलाकों में सीधे आमने - सामने हो कर शीघ्र परिणाम के बजाय दीर्घकालिक रणनीति पर काम करना होगा। शहरी इलाकों में पार्टी के लोगों को हमलावर न हो कर रक्षात्मक ढंग से काम करना होगा। इसके लिए धैर्य के साथ काम करना होगा। सभी कॉमरेडों की पहचान को गुप्त रखने के लिए अधिक से अधिक सावधानी बरतनी होगी। हमारा भूमिगत ढांचे के बारे में पता न चले यह सुनिश्चित करना होगा अन्यथा यह पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है।

शहरी कार्य के प्रमुख उद्देश्य

इस दस्तावेज के अनुसार शहरी इलाके में कार्य को तीन मुख्य उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला व प्रमुख काम है कि आम जनता को इकट्ठा व संगठित कर पार्टी को उसके आधार पर तैयार करना। जन समुदाय, छात्र, श्रमिक, मध्यम वर्गीय नौकरीपेशा लोग व बुद्धिजीवियों को प्रेरित व संगठित करना।

दूसरा, संयुक्त मोर्चा तैयार करना यानी मजदूरों को इकट्ठा कर शहरों में अन्य वर्गों के साथ गठबंधन स्थापित करना। किसान व श्रमिकों के बीच एकता स्थापित करना इसका दूसरा उद्देश्य है।

किसानों व शहरी इलाके में कार्य का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामरिक कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में सामरिक कार्य

करने का कार्य मूल रूप से पीजीए व पीएलए का है लेकिन ग्रामीण इलाकों में कैडरों को भेजना आदि काम शहरी आंदोलन का है। इसके अलावा शत्रु के रैंक में घूसपैठ व लाजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना भी इसमें शामिल है। सभी वर्गों को संगठित व प्रेरित कर व्यापक जनक्रांति की तैयारी करना व अंत में सशस्त्र क्रांति को अंजाम देना जैसाकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके सहयोगी नक्सलवादी चला रहे हैं। इसमें स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि पहला उद्देश्य यानी लोगों को संगठित व प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बिना शेष दो उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है।

विभिन्न प्रकार के जन संगठन खडा करना

इस दस्तावेज में शहरी कार्य में विभिन्न प्रकार के जन संगठन तैयार करने के बारे में उल्लेख किया गया है। 1. गुप्त क्रांतिकारी जन संगठन 2. खुला व आधा खुला क्रांतिकारी संगठन 3. खुला कानूनी जन संगठन। तीसरे प्रकार के संगठनों का पार्टी के साथ सीधे तौर पर संबंध नहीं रहेगा। तीसरे प्रकार के संगठनों को भी तीन और प्रकार से फ्रैक्शनल वर्क, पार्टली फार्मज कवर आर्गनाइजेशन व लिगल डेमोक्रेटिक आर्गनाइजेशन के रुप में विभाजित किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार शहरी नक्सलों का यह तीसरे प्रकार का संगठन देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक है। इसका कारण है कि इस प्रकार का कानूनी संगठन नजरों से बच कर 'स्टेट' के खिलाफ धूर्ततापूर्ण व कपटी शिकायतों के जरिये लोगों का समर्थन हासिल करते हैं तथा संवैधानिक प्रभुत्व को खत्म करने का प्रयास करते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर के दो प्रकार के संगठनों की पहचान की जा सकती है तथा कानून के अनुसार उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन इस तरह के संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं होता। क्योंकि कभी इस प्रकार के संगठनों या संगठनों को चलाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होने पर विभिन्न प्रकार के मानवाधिकार, दलित अधिकार व उत्पीड़न विरोधी बताने वाले लोग सामने आकर हल्ला मचाते रहते हैं तथा कहते हैं मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है।

दस्तावेज के अनुसार विभिन्न प्रकार के संगठन जैसे ट्रेड यूनियन, मानवाधिकार संगठन, छात्र, महिला संगठन, जाति हटाओ संगठन, सांस्कृतिक संगठन, सांप्रदायिक सौहार्द संगठन आदि संगठनों का गठन कर इन कार्यों को शहरी इलाकों में किया जा रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब, जिम्नासियम, भजन मंडल, गैर सरकारी कल्याण संगठन, जाति संगठन, अल्पसंख्यक संगठन के नाम पर भी शहरी इलाकों में नक्सली कार्य करना होगा।

इस दस्तावेज में शहरी कार्य में विभिन्न प्रकार के जन संगठन तैयार करने के बारे में उल्लेख किया गया है। 1- गुप्त क्रांतिकारी जन संगठन २- खुला व आधा खुला क्रांतिकारी संगठन ३. खुला कानूनी जन संगठन। तीसरे प्रकार के संगठनों का पार्टी के साथ सीधे तौर पर संबंध नहीं रहेगा। तीसरे प्रकार के संगठनों को भी तीन और प्रकार से फ्रैक्शनल वर्क, पार्टली फार्मज कवर आर्गनाइजेशन व लिगल डेमोक्रेटिक आर्गनाइजेशन के रुप में विभाजित किया जा सकता है।

शत्रु के शिविर में घुसपैठ

इस दस्तावेज में कहा गया है कि शहरी इलाकों में पार्टी के कार्य में एक प्रमुख कार्य शत्रु के शिविर में घुसपैठ है। सामरिक बलों के साथ साथ अर्ध सामरिक बल, पुलिस तथा प्रशासनिक मशीनरी के उच्च स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों में घुसपैठ अत्यंत जरुरी है। इन लोगों से शत्रु के गतिविधियों गुप्त सूचना प्राप्त करना, क्रांति के लिए समर्थन जुटाना तथा शत्रु शिविर से आवश्यक होने पर विद्रोह कराना आदि कार्य किया जाएगा।

शहरी इलाकों से कैडर ग्रामीण इलाकों में भेजना

दस्तावेज के अनुसार जनयुद्ध व ग्रामीण इलाकों में आंदोलन के लिए शहरी कैडरों को ग्रामीण इलाकों में भेजना अत्यंत जरुरी है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए असंगठित क्षेत्र में कार्य का होना अत्यंत जरुरी है। दस्तावेज के अनुसार रणनीतिक कारणों से प्रमुख

उद्योगों में पार्टी का कार्य निश्चित रुप से जरुरी है लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम को गति देना जरुरी है क्योंकि यहां से कैडर निकाल कर ग्रामीण इलाकों में आंदोलन में भेजा जा सकता है।

सशस्त्र युद्ध के लिए लाजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना

दस्तावेज में कहा गया है कि शत्रु समस्त प्रकार का लाजिस्टिक सपोर्ट शहरों से प्राप्त करता है। पीपुल्स आर्मी ग्रामीण इलाकों से तथा ग्रामीण जनता पर ही अपने आवश्यकता पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजों के लिए शहरी क्षेत्रों से सहयोग की आवश्यकता रहती है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में पार्टी की शक्ति को ध्यान में रख कर ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलवादियों को सहायता करने का उल्लेख इसमें है जो चीजें केवल शहरों में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए हथियार व गोलाबारुद उपलब्ध कराना व मेडिकल की सुविधा आदि उपलब्ध कराना है।

भारत के आम लोगों को अर्बन नक्सलियों के भारत को समाप्त करने की भंयकर योजना के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है। ये लोग मीडिया व अन्य उपकरणों के जरिये मानवाधिकार व वंचित अधिकारों के नाम पर मसीहा की छवि बनाया हुआ है। यह छवि तब टूटेगी जब भारत की आम जनता को इस सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। इसलिए अर्बन नक्सलियों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरुक करने की आवश्यकता है।

यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्नन गंसाल्वेस जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है उन्हें पिछले दिनों नागपुर के एक सेशस्न कोर्ट ने हथियार रखने के आरोप में दोषी पाया था। इसका मतलब यह है कि गंसाल्वेस भाकपा (माओवादी) पार्टी के अर्बन पर्सेपेक्टिव के अनुसार कार्य कर रहे थे।

इसी तरह कई बार पुलिस के साथ एनकाउंटर के दौरान ग्रामीण कैडर घायल हो जाते हैं, या फिर कई बार कैडर बीमार पड जाते हैं। उनका इलाज उनके कार्यक्षेत्र या जंगलों में संभव नहीं होता। ऐसे में शहरी नक्सलों की जिम्मेदारी बन जाती है उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना। इसका उल्लेख भी इस दस्तावेज में है। दस्तावेज में कहा गया है कि इसके लिए समर्थक डाक्टरों का नेटवर्क खडा करना तथा ग्रामीण इलाकों में घायल या बीमार नक्सली को शहरों के अस्पतालों में चिकित्सा की व्यवस्था करना आदि कार्य शहर में रहने वाले कैडरों को करना होगा। इसी तरह युद्ध हथियार, संचार व अन्य उपकरणों के मरम्मत के लिए भी शहर से ही सहयोग देनी होगी। इसके लिए शहरों में कैडर तैयार करना उन्हें ग्रामीण इलाकों में भेज कर जन युद्ध लड रहे कैडरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी होगी।

अर्बन नक्सल अपना काम पूरी तरह से मानवाधिकार व वंचित लोगों के अधिकारों की आड़ में करते हैं। वे भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते लेकिन संविधान से प्राप्त हर अधिकार का बखूबी इस्तेमाल कर भारत को ही समाप्त करने के लिए लगे रहते हैं।

इन अर्बन नक्सल का इको सिस्टम बडा जबरदस्त है। छत्तीसगढ में एक अर्बन नक्सली डा विनायक सेन पर माओवादियों के साथ देने तथा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। न्यायालय में मामला चला तथा न्यायालय ने डा सेन को दोषी करार दिया। इन शहरी नक्सलों का नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि देश के अनेक नामी गिरामी लोग तत्काल उन्हें रिहा करने की मांग को लेकर कैंडल लाइट मार्च निकालने लगे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो 12 देशों के 40 नोबेल विजेता विनायक सेन के एक पिटिशन पर हस्ताक्षर कर विनायक सेन को रिहा करने की मांग की। अंत में उन्हें रिहा करना पडा। अभी हाल ही की घटना भी अर्बन नक्सलियों के जबरदस्त इको सिस्टम को प्रमाणित करता है।

भारत के आम लोगों को अर्बन नक्सलियों के भारत को समाप्त करने की भंयकर योजना के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है। ये लोग मीडिया व अन्य उपकरणों के जरिये मानवाधिकार व वंचित अधिकारों के नाम पर मसीहा की छवि बनाया हुआ है। यह छवि तब टूटेगी जब भारत की आम जनता को इस सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। इसलिए अर्बन नक्सलियों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरुक करने की आवश्यकता है। ■

(लेखक माओवाद व मीडिया विषय के शोधार्थी हैं)

नक्सलियों ने जिल्लत के सिवा क्या दिया आदिवासियों को

। आशीष कुमार 'अंशु' ।

अर्बन नक्सल पर बात करते हुए कई बार इसे समझा पाना कठिन इसलिए होता है क्योंकि अर्बन नक्सल को परिभाषित किए बिना हम इस पर बातचीत प्रारम्भ कर देते हैं और फिर इससे हर एक व्यक्ति को यह आजादी मिल जाती है कि वह इसकी अपनी परिभाषा गढ़ पाए। इससे उन मुट्ठी भर लोगों को भी अवसर मिल जाता है जो नक्सलियों से सहानुभूति रखते हैं और मीअर्बननक्सलटू का हैस टैग सोशल मीडिया पर चल जाता है। इस तरह वापपंथी गिरोह द्वारा प्रयास किया जाता है कि अर्बन नक्सल जैसे गम्भीर आरोप की गम्भीरता को कम कर दिया जाए। जबकि 125 करोड़ की आबादी में दस हजार लोग चाहकर किसी भी हैस टैग को ट्रेन्ड करा सकते हैं। 125 करोड़ की आबादी में यह दस हजार की संख्या मुट्ठी भर की होती है। लेकिन इनके अंदर नक्सलियों के लिए जो सहानुभूति देश के कथित बुद्धीजीवी वर्ग के माध्यम से बोई जा रही है, वह बेहद खतरनाक है।

अर्बन नक्सल पर बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले 21 सितम्बर को रायपुर से गोंडवाना एक्सप्रेस लौटते हुए मिले उस शिक्षक का जिक्र महत्वपूर्ण जान पड़ता है जिसने बताया कि वह मंडला के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाता है। बातचीत के दौरान उसने बस्तर में सीआरपीएफ के अत्याचार की कहानी सुनाई और एक महिला जिस पर नक्सलियों का प्रतिनिधि बनकर पैसों के लेन—देन का आरोप है और जो बस्तर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ चुकी है का जिक्र करते हुए उसने न्याय की बात की। उस शिक्षक का कहना था कि जब उस महिला को न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय के लिए संघर्ष का ही रास्ता शेष बचेगा ना? शिक्षक ने बताया कि आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए चालीस लोगों की टीम वहां काम कर रही है। जब मैंने पूछा कि वे कौन लोग हैं? उसने बताने से इंकार कर दिया।

इस घटना का जिक्र इसलिए यहां महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक वह सार्वजनिक तौर पर नक्सलियों और उनके प्रतिनिधियों के प्रति इस तरह सहानुभूति जता रहा है। वह अपने छात्रों को वर्ग में क्या बताता होगा? जब एक पुलिस वाला अत्याचार करता है, उसके खिलाफ हम और आप न्यायालय में जा सकते हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन ऐसे लोगों पर संदेह तब होता है, जब वे सिर्फ पुलिस और व्यवस्था पर चोट पहुंचाते हैं लेकिन नक्सलियों के अत्याचार पर खामोशी थाम लेते हैं।

नक्सलियों के पक्ष में उन्हें नैतिक समर्थक देने वाला एक समुदाय जिला मुख्यालयों और महानगरों में बैठा है। वह पत्रकार, सीविल सोसायटी एक्टिविस्ट, वकील, प्राध्यापक किसी भी वेश में हो सकता है। इनका प्रभाव समाज के बड़े वर्ग पर होता है और ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल नक्सली घटनाओं को सही ठहराने के लिए करते रहे हैं। यह इन शहरी नक्सलियों के नेटवर्क का ही कमाल है कि समाज में नक्सलियों की छवि रॉबिनहूड की बनी है। जो अमीरों से लूटकर गरीबों को देता है। जबकि बस्तर का अनुभव है कि नक्सली अमीरों को लूटता जरूर है लेकिन गरीबों को देता नहीं है। हां उनके बीच जिसने अधिकार की बात की, उसकी बेरहमी से हत्या जरूर करता है। बस्तर में तीस से अधिक साल हो गए नक्सलियों को अपने पांव जमाए हुए। क्या बदला बस्तर के अंदर नक्सलियों के राज में?

माओवादियों की एक कहानी और शुरू करते हैं अगस्त 2008 में बिहार में आई भयानक बाढ़ से। बताया गया था कि नेपाल का कुसहा बांध टूटने की वजह से यह बाढ़ आई है। यही वह साल था, जब पहली बार मेरा परिचय 'अर्बन नक्सल' शब्द से हुआ था। बिहार में बाढ़ का पानी उतर चुका था। एक शाम 'बाढ़ मुक्ति अभियान' के संयोजक दिनेश कुमार मिश्र का फोन आया। टिकट भिजवा दिया है, पटना आना है। उनके आदेश के बाद पटना पहुंच गया। वास्तव में देश के एक दर्जन पत्रकारों के साथ बिहार की बाढ़ की त्रासदी को समझने के लिए पांच दिनों की यह एक यात्रा थी। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में कोलकाता से कॉमरेड संकर रॉय, दिल्ली से राकेश भट्ट और हिमांशु उपाध्याय, पूणे से अभिजीत घोडपड़े, मुम्बई से नितिन चन्द्रा जैसे कई फिल्मकार और पत्रकार शामिल हुए थे। इसी यात्रा में नेपाल की सीमा में प्रवेश करते ही एक व्यक्ति हमारी गाड़ी में आ चढ़ा था। वह हमारे बीच नेपाल का प्रतिनिधि और पूरी यात्रा में मार्गदर्शक बना। यात्रा के दौरान उसने अपना परिचय खुद ही दिया कि वह माओवादी है। एक प्रतिबंधित संगठन का नेता हमारी गाड़ी में था, मुझे थोड़ा असहज होता देखकर उसने ही बताया कि माओवादी भारत में प्रतिबंधित हैं लेकिन नेपाल में हमारी सरकार है। उन दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री माओवादी नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड हुआ करते थे।

फिर तो अच्छी दोस्ती हुई। लंबी बातचीत भी। और माओवादियों के कामकाज को समझने का अवसर भी मिला। माओवादी नेता ने बताया कि उनके यहां तीन स्तरीय व्यवस्था है। माओवादी सेना के लोग जंगल मे रहते हैं। वहां अभ्यास करते हैं और हमले की रणनीति बनाते हैं। उनके लिए धन लाना और तैयारी के संबंध में धन मुहैया कराने वालों तक जानकारी पहुंचाने का काम एक छोटा समूह करता है। जिसका जंगल और महानगर के बीच जाना - आना लगा रहता है। वह जंगल की खबर शहर तक और शहर की खबर जंगल तक पहुंचाता है।

उसने यह बात बड़बोलेपन में ही कही थी कि - ''जल्दी ही दिल्ली के लालकिले पर जब हमारा झंडा लहराएगा, उसके बाद तुम देखकर चौंक जाओगे कि कौन - कौन और कैसे - कैसे लोग हमारे साथ हैं?''

उस माओवादी की बात अर्बन नक्सलियों के नाम पर देश में हुई गिरफ्तारियों के बाद बार - बार याद आती है, ''चौंक पड़ोगे।'' वास्तव में जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, वह चौंकाने वाले ही हैं। और सच कहूं तो नहीं भी हैं। अपने आस - पास घट रही घटनाओं को लेकर जो चौकस हैं, वह बिल्कुल इन नामों को सुनकर नहीं चौंकेंगे क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, नक्सलियों से संबंध का उनका पुराना इतिहास रहा है।

मेरे ही सवाल के जवाब में एक और बात उस माओवादी नेता ने बताई थी, जिसका उल्लेख यहां महत्वपूर्ण जान पड़ता है। सवाल था, ''चीन आपलोगों को हथियार से मदद क्यों कर रहा है? क्या आप लोग चीन के उद्देश्य की पूर्ति भारत में कर रहे हैं?''

उस माओवादी ने स्वीकार किया कि वे चीन का हथियार इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका कहना था कि हथियार की खरीद वह सरकार से नहीं करता। उनके पास चीन का जो हथियार है, वह अवैध है और उस हथियार को वे पैसे देकर खरीदते हैं।

मेरा अगला सवाल था - ''हथियार खरीदने के लिए इतना पैसा कहां से आता है?''

उसने मुस्कुराते हुए - संक्षिप्त सा जवाब दिया - ''दिल्ली से।''

यह मेरा पहला परिचय माओवाद के महानगरीय रिश्ते से था। इसका मतलब स्पष्ट था कि कुछ ऐसे लोग दिल्ली में मौजूद थे जो राजधानी में बैठकर ना सिर्फ नेपाल के माओवादियों को धन मुहैया करा रहे थे बल्कि वे नेपाल के जंगलों में चल रही माओवादी

गतिविधियों में दखल भी रखते थे। इस बात को अधिक बल मिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के उस कांग्रेसी नेता से मिलकर जिसने नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की योजना बना ली थी।

सलवा जुडूम सफल भी हो रहा था लेकिन नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क की सक्रियता की वजह से ना सलवा जुडूम और ना ही महेन्द्र कर्मा अपना उद्देश्य हासिल कर पाए। सलवा जुडूम पर न्यायालय ने रोक लगा दी और महेन्द्र कर्मा नक्सलियों की गोलियों से छलनी कर दिए गए। महेन्द्र कर्मा ने बताया था, ''यदि आंदोलन में इतनी खामियां थीं तो हम जो शीर्ष नेतृत्व में थे, एक भी शिकायत, एक भी एफआईआर मेरे खिलाफ क्यों नहीं आई? हत्या, बलात्कार, लूट का आरोप सलवा जूडूम पर लगता रहा, हम तो आन्दोलन की अगली पंक्ति में थे, मुझ पर यह आरोप क्यों नहीं लगे?''

नक्सलियों का अर्बन नेटवर्क सलवा जुडूम के समय अति सक्रिय हो गया था। यदि मनमोहन सिंह की सरकार उस समय अपनी मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय दे देती तो आज अर्बन नेटवर्क को लेकर पूरे देश में यह विमर्श ना खड़ा हुआ होता।

दिवंगत महेन्द्र कर्मा ने बताया था - "नक्सलियों की ताकत बंदूक में नहीं है। उनकी नेटवर्किंग में है। ये ज़माना नेटवर्किंग का है। जिस नेता की नेटवर्किंग जितनी अच्छी, वह उतना बड़ा नेता है। सफल नेता है। सलवा जुडूम के माध्यम से उनका नेटवर्क कमजोर हो रहा था। उनके नेटवर्क का आदमी उन्हें छोड़कर मुख्य धारा में आ रहा था। हम उनका नेटवर्क कमजोर करके ही उन्हें मार सकते थे। उन्होंने उस दौरान अपवादों को मीडिया में इस तरह उठाया जैसे पूरे बस्तर में यही हो रहा है। और वे सफल हुए।''

नक्सलियों को लेकर जैसे ही सरकार कोई एक्शन लेती है, दिल्ली में एक बड़ा वर्ग है जो सक्रिय हो जाता है। कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब से लेकर जन्तर मंतर पर चहल - पहल बढ़ जाती है। कई चेहरे तो ऐसे हैं, जो नक्सलियों के प्रति अपनी सहानुभूति को छुपाते तक नहीं। कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी जाहिर कर देते हैं।

नक्सलियों से जुड़ी खबरों को लेकर यह बात अरूंधति राय, राहुल पंडिता, से लेकर आलोक पुतुल तक मानेंगे कि बस्तर की खबर आम खबरों की तरह बस्तर से रायपुर तक का सफर तय नहीं करती। बस्तर की खबर पहले किसी अंतरराष्ट्रीय - राष्ट्रीय अखबार - चैनल की खबर बनती है। उसके बाद रायपुर में उसका फॉलोअप छपता है। फिर सबसे अंत में जगदलपुर संस्करण में वह खबर पढ़ने को मिलती है। क्या यह संभव है बिना उस तार के जो महानगर में बैठे नक्सली को जंगल में बैठे नक्सली से जोड़ता हो।

बात सिर्फ तार की नहीं है, हिस्सेदारी की भी है। जिस पर विस्तार से बात करते हैं बस्तर के पूर्व आईजी एसआरपी कल्लूरी। बकौल कल्लूरी - "बस्तर से नक्सली सालाना 1100 करोड़ रूपए की वसूली करते हैं। यह पैसा उन माओवादियों को नहीं मिलता जो हथियार लेकर जंगल में आंधी - पानी और मलेरिया से जुझ रहा है। यह पैसा पहुंचता है नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क के पास। ये एक छोटा सा वर्ग है जो गैर सरकारी संगठन के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, अध्येता या शोधार्थी के नाम पर इस दावे के साथ बस्तर में मौजूद होता है कि हम वहां काम कर रहे हैं। इस शहरी नेटवर्क का काम वहां नक्सलियों के मामले पर न्यायालय में लड़ना। सुरक्षा बलों पर बलात्कार का मुकदमा करवाना भर है। स्थानीय लोगों के जीवन में उनकी मौजूदगी से कोई परिवर्तन आया हो, ऐसा प्रयास मैने बस्तर के अपने पूरे कॅरियर में इनकी तरफ से नहीं देखा।''

कल्लूरी यह भी कहते हैं - "अर्बन नक्सली संख्या में बेहद कम हैं लेकिन शक्तिशाली हैं। वे अपने झूठ के दम पर पूरी दुनिया में बस्तर की एक छवि गढ़ने में कामयाब हुए हैं। इसलिए मैं बस्तर को इन अर्बन नक्सलियों की नजर से देखने की जगह बस्तर आकर देखने का ही सुझाव सभी को देता हूं।''

बहरहाल, नक्सली कहते हैं कि वे आदिवासी के हक के लिए लड़ते हैं और बस्तर में जिन लोगों की हत्या नक्सलियों ने की, उनमें 99 फीसदी आदिवासी ही थे। बस्तर के नक्सलियों के संबंध में यह जानना आवश्यक है कि वहां के नक्सली वास्तव में नक्सली नहीं हैं। वह पीड़ित हैं। उसका शोषण हैदराबाद और महाराष्ट्र के नक्सली कर रहे हैं। बस्तर के नक्सली जो जंगल में हथियार लेकर खड़े हैं वे मजदूरी करने के लिए और सीआरपीएफ की गोली खाने के लिए रखे गए हैं। उनको बस्तर की 1100 करोड़ की वसूली में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती क्योंकि उस पैसे का बड़ा हिस्सा नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के पहुंच जाता है। ■

(लेखक घुमंतू पत्रकार हैं)

ममता की निर्ममता, छात्रों को शिक्षक के बदले मिली मौत

| अजीत कुमार सिंह |

'हम में उर्दू शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, हम पिछले दो साल से बंगाली और विज्ञान शिक्षक की मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी भविष्य को देखते हुए उर्दू शिक्षक के बजाय बंगाली और विज्ञान के शिक्षक को भेंजे' - यही तो मांग किया था पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर के दारवीट क्षेत्र के छात्रों ने... बार बार की मांग के बाद भी जब शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों के इस मांग से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इतनी निर्मम हुई कि शिक्षक के बदले उन्हें मौत की नींद दे दी और राजेश एवं तापस सदा के लिए खामोश हो गया। तापस और राजेश के पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि अपने बेटे के शव को कंधा देना पड़ेगा, उन्हें कहां पता था स्वामी विवेकानंद, गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे विद्वानों की धरती पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग, उनके बेटों के लिए मौत का कारण बन जायेगा। अब दोनों के मां - बाप अपने बच्चों की मौत के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए दर - दर भटक रहे हैं। उनके बच्चों का पोस्टमार्टम भी उन्हें अंधेरों में रख कर किया गया, सही पोस्टमार्टम की जांच के लिए आज भी वे अंतहीन खामोश लेटे अपने बेटे के शव को संभाले बैठे है।

क्या है मामला ?

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के दारीवीट गांव के विद्यालय में 2000 हजार से अधिक छात्र हैं, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को घोर कमी है, विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति को इसी से आंका जा सकता है कि वहां पर शिक्षक की जगह लीपिक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। छात्रों की यह मांग थी कि उन्हें बंगाली और गणित के शिक्षक दिये जाएं ताकि वे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा एक शिक्षक की नियुक्ति की

गई जो उर्दू भाषा में पढ़ाते थे, जबकि वहां पर पढ़ने वाले अधिकांश छात्र बंगाली भाषी थे, वे लोग अपनी पढ़ाई बंगाली भाषा में करना चाहते थे। लंबे समय से विज्ञान, गणित और बंगाली के शिक्षक विद्यालय में नहीं था, छात्र लगातार इन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग कर रहे थे परंतु उन्हें मिला उर्दू शिक्षक। विद्यालय प्रबंधन के इस फैसले से छात्र नाराज हो गये और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। छात्रों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अगले ही दिन पूरे लाव - लश्कर के साथ उर्दू शिक्षक विद्यालय में योगदान करने आये जिसमें कथित रूप से कुछ असामाजिक तत्त्व भी मौजूद थे। प्रबंधन के वादा - खिलाफी के विरूद्ध छात्र प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय लोग और अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक मोनिका चौधरी के मुताबिक योगदान करने आये उर्दू शिक्षक के लाव लश्कर एवं पुलिस के द्वारा प्रदर्शन कर रही छात्राओं को भद्दी - भद्दी गालियां दी जाने लगी और छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसकी खबर लगते ही राजेश सरकार और तापस बर्मन ने छात्राओं के साथ की जा रही बदसलूकी का विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और लाठियां ही नहीं भांजी बल्कि गोलीबारी शुरू कर दी, गोलीबारी में राजेश सरकार की मौत हो गई और तापस बर्मन बुरी तरह घायल हो गये। अगले दिन अस्तपाल में तापस को भी मृत घोषित कर दिया गया । राजेश और तापस की मृत्यु के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने ममता सरकार की निरकुंशता और दमनकारी पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया।

वकीलों और विद्यार्थियों के छः सदस्यीय दल ने इस्लामपुर के दारीवीट गांव पहुंचकर लिया जायजा

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के दारीवीट गांव में 20 सितंबर को पुलिसिया गोलीबारी में हुई दो छात्रों, राजेश एवं तापस के मौत की जानकारी मिलने के बाद 28 सितंबर को दिल्ली से वकीलों और विद्यार्थियों के छः सदस्यों का एक दल दारीवीट गांव की परिस्थितियों का जायजा लेने पहुंचा था। वहां से लौटने के बाद दल के सदस्यों ने जो बातें बताई वह चौंकाने वाले थे। दल के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता कर दिल्ली में इसकी जानकारी दी। दल में शामिल सदस्यों और विद्यार्थी परिषद् ने मांग की है कि मृतकों के परिवार को तुरंत सहायता के तौर पर आवश्यक मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही मृतकों के पुनः पोस्टमार्टम करने की मांग भी की गई है। पूरे मामले में मृतक के परिवार ने सीबीआई से जांच कराए जाने की केंद्र सरकार से मांग की है।

दारीवीट गये जांच दल के सदस्यों की मानें तो वहां के विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था लचर स्थिति में है तथा विद्यार्थी शिक्षकों की कम एवं अनियमित कक्षाओं की समस्या से जूझ रहे हैं। विद्यार्थी - शिक्षक अनुपात अत्यंत दयनीय है तथा लगभग 2000 विद्यार्थियों पर 20 से कम शिक्षक हैं तथा लिपिकों द्वारा भी अध्यापन कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से विरोध जताया जा रहा था लेकिन विद्यालय प्रशासन द्वारा उनकी मांग अनसुनी की जाती रही।

बंगाली की जगह जबरन उर्दू शिक्षक को नियुक्त करने का प्रयास

पश्चिम बंगाल से लौटे दल ने बताया कि 18 सितंबर को जब विज्ञान व गणित के शिक्षकों के स्थान पर विद्यालय प्रशासन द्वारा भाषा के शिक्षक के प्रभार लेने की प्रक्रिया के आरंभ होने पर विद्यार्थियों द्वारा विरोध किया गया, जिस पर प्रबंधन समिति के सदस्यों, प्रधानाचार्य व डीआईओएस द्वारा छात्रों को लिखित आश्वासन दिया गया कि उर्दू शिक्षक के स्थान पर प्रशासन द्वारा उन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जिनकी विद्यार्थियों को आवश्यकता है । इस आश्वासन के बाद जब 20 सितंबर को जबरन उर्दू शिक्षक नियुक्त कराने का प्रयास किया गया तो विद्यार्थियों ने विरोध किया।

छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की कोशिश

पत्रकार वार्ता में दल ने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन के दमन हेतु भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल द्वारा छात्राओं के प्रति भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। पुलिस इस सीमा तक आक्रामक और दमनकारी थी कि नाबालिग बच्चों पर सिर्फ आंसू गैस के गोले और लाठियां ही नहीं बल्कि गोलियां भी चलाई गईं, जिसमें राजेश सरकार एवं तापश बर्मन की मृत्यु हो गई था बिप्लव सरकार गंभीर रूप से घायल हो गये, जिनका ईलाज चेन्नई के एक अस्पताल में हो रहा है। अभाविप की मीडिया संयोजक मोनिका चौधरी ने

बताया कि प्रदेश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनता का सहयोग करने व निष्पक्ष जांच के स्थान पर पीड़ित जनता को ही डराया और धमकाया जा रहा है तथा घर की महिलाओं को बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं.

लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास: अभाविप ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार की पुलिस का यह निंदनीय कृत्य सरकार के घृणित चेहरे को उजागर करता है। साधारण छात्रों पर इस सीमा तक का बल प्रयोग व मासूमों की निर्मम हत्या स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। वर्तमान प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच संभव नहीं है अतः पीड़ितों को न्याय प्राप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाय। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम जिन संदिग्ध परिस्थितियों में किया गया है उसे देखते हुए पुनः पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक हो जाता है। परिवार ने सीबीआई जांच और पुनः पोस्टमार्टम की बात को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया है तथा मृतकों की समाधी बना दी है। तथा जल्द से जल्द इस विषय में कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा हो।

> छात्रों के मांग से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इतनी निर्मम हुई कि शिक्षक के बदले उन्हें मौत की नींद दे दी और राजेश एवं तापस सदा के लिए खामोश हो गया। तापस और राजेश के पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि अपने बेटे के शव को कंधा देना पड़ेगा, उन्हें कहां पता था स्वामी विवेकानंद, गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे विद्वानों की धरती पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग उनके बेटों के लिए मौत का कारण बन जायेगा। अब दोनों के मां - बाप अपने बच्चों की मौत के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए दर - दर भटक रहे हैं। उनके बच्चों का पोस्टमार्टम भी उन्हें अंधेरों में रख कर किया गया, सही पोस्टमार्टम की जांच के लिए आज भी वे अंतहीन खामोश लेटे अपने बेटे के शव को संभाले बैठे है।

छात्रों की मौत के खिलाफ अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के दारीवीट विद्यालय में निर्दोष छात्रों की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने 25 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन किया। कोलकाता में मार्च कर रहे अभाविप के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। मार्च का नेतृत्व कर रहे अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जिन्हें देर शाम तक रिहा कर दिया गया। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय के छात्रों पर इस तरह का जघन्य अत्याचार असहनीय है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी तक इस विषय पर कोई ठोस कदम न उठाया जाना बेहद आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। अभाविप इस घटना के जिम्मेदार जिला पुलिस अधीक्षक को तुरंत बर्खास्त करने की मांग करती है और अगर दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तक तो विद्यार्थी परिषद् कोलकाता से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करेगी। निर्दोष मारे गये छात्रों की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कठोरतम सजा की मांग को लेकर अभाविप ने कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, भुवनेश्वर, दिल्ली, रोहतक, चंडीगढ़, जयपुर, श्रीनगर, शिमला, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मुंबई, पुणे, नागपुर, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाई, त्रिवेन्द्रम, बैंगलुरू, विजयवाड़ा, गुवाहाटी समेत देश के विभिन्न भागों में जोरदार प्रदर्शन किया ।

दिल्ली में रैली को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि सरकार ने दारीवीट विद्यालय में पुलिसया बर्बरता के खिलाफ जिस प्रकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है वह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने में संलिप्त है। बांग्ला की जगह उर्दू थोपकर सरकार केवल और केवल तुष्टिकरण को बढ़ावा दे रही है। यह मात्र दो छात्रों की नहीं बल्कि समस्त बांग्ला अस्मिता की लड़ाई है। जिस भूमि पर रवीन्द्र नाथ टैगोर जी जैसे महापुरूषों का जन्म हुआ उस भूमि पर बांग्ला भाषा को दबाने के उद्देश्य से उर्दू भाषा विद्यार्थियों पर थोपना ममता सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। मृतक छात्रों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और इस घटना की सीबीआई जांच तथा पुलिसकर्मियों के बर्खास्त होने तक हमारी लड़ाई पूरे देश में जारी रहेगी। ■

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अभाविप ने लहराया जीत का परचम

अभाविप ने अध्यक्ष समेत तीन पदों पर कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) को करारी शिकस्त दी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) एवं वामपंथी संगठन आईसा के संयुक्त गठनबंधन के प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डूसू) छात्र संघ चुनाव में जीत का परचम लहराया है। अभाविप ने अध्यक्ष समेत तीन पदों पर कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) को करारी शिकस्त दी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) एवं वामपंथी संगठन आईसा के संयुक्त गठनबंधन के प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सीवाईएसएस/आईसा के प्रत्याशी तीन पदों पर तीसरे स्थान पर रहे वहीं सचिव पद पर नोटा से भी पिछड़ गये। इस बार हुए छात्र संघ चुनाव में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल 1.35 लाख छात्रों में से 44.46 प्रतिशत छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा 52 केन्द्र बनाये गये थे। डूसू चुनाव में अभाविप के अंकिव बसोया, शक्ति सिंह और ज्योति चौधरी ने क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सह सचिव पदों पर जीत

छात्रों के दस्तावेज की जांच करना, विश्वविद्यालय का काम – भरत खटाना

अभाविप की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए विद्यार्थी परिषद् के दिल्ली प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने कहा कि यह जीत 365 दिन परिसर में अनवरत छात्रों के हित के लिए खड़े रहने वाले छात्र संगठन अभाविप के प्रति छात्रों का विश्वास है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर बरसाती मेढ़क के समान आये छात्र संगठनों को नकार दिया है, परिणाम से स्पष्ट है कि अभाविप ही एक मात्र ऐसा संगठन है जो छात्र हितों के लिए संघर्ष करती है। वहीं एनएसयूआई के द्वारा अंकिव बसोवा की डिग्री पर उठाये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनएसयूआई अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, जिस कारण कभी ईवीएम में गड़बड़ी की बात करती तो कभी कुछ...। ईवीएम पर जब दाल नहीं गली तो अंकिव बसोया के डिग्री पर सवाल उठाने लगे। भरत खटाना ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंकिव बसोया के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरांत ही उन्हें प्रवेश दिया है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने यहां दाखिला लिये किसी भी छात्र के दस्तावेजों को सत्यापित करने का अधिकार है। एनएसयूआई का यह काम नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्रदान करे या सत्यापित करे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए डीयू प्रशासन को न केवल अंकिव के दस्तावेजों को सत्यापित करे, बल्कि उन्हें भविष्य में अफवाहें को रोकने के लिए सभी डूसू पदाधिकारियों के दस्तावेजों को सत्यापित करने की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहुंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने यहां दाखिला लिए सभी छात्रों के कागजात को फिर से सत्यापित करें, ऐसा करने से कई संगठन के पदाधिकारियों के भी चेहरे बेनकाब होंगे, चूंकि एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की डिग्री भी संदेह के घेरे में है जिसकी जांच होना जरूरी है।

दर्ज की वहीं सचिव पद पर एनएसयूआई के आकाश चौधरी ने जीत हासिल की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा घोषित छात्र संघ चुनाव 2018 के परिणाम के अनुसार अध्यक्ष पद पर अभाविप के अंकिव बसोया को 20,467 मत प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी सनी छिल्लर को 1724 मतों के अंतर से पराजित किया है, सनी को कुल 18,743 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं अभाविप के शक्ति सिंह ने मतों को शक्ति से सबको चकित कर दिया है, शक्ति को सबसे ज्यादा 23,046 मत प्राप्त हुए हैं जबकि उनके प्रतिद्वंदी लीना को मात्र 15,373 मत मिले हैं। सह सचिव पद पर अभाविप की ज्योति चौधरी ने 4972 मतों से एनएसयूआई के सौरभ यादव को हराया है, ज्योति को 19,353 मत मिले हैं जबकि सौरभ को 14,381 मत पाकर ही संतुष्ट होना पड़ा। इसके अलावा एनएसयूआई के आकाश चौधरी ने अभाविप के सुधीर को हराकर सचिव पद पर कब्जा किया है। सचिव पद पर आकाश को 20,198 मत प्राप्त हुए हैं वहीं अभाविप के सुधीर को 14,109 मत मिले हैं। इस चुनाव में सबसे रोचक मुकाबला दो साल बाद उतरी आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई सीवाईएसएस एवं वाम संगठन आईसा के संयुक्त गठबंधन और नोटा के बीच देखने को मिला। आईसा/सीवाईएसएस के गठबंधन को नोटा ने सचिव पद पर जबरदस्त पटखनी दी है। सचिव पद पर नोटा को जहां 6810 वोट मिले हैं वहीं पर सीवाईएसएस/आईसा गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रमणि को मात्र 4,582 वोट मिले हैं। हांलाकि सचिव पद को छोड़ दें तो अन्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सह सचिव पद पर संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के चार पदो पर कुल 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। इस चुनाव में छात्रा सुरक्षा, विश्वविद्यालय के छात्रों के परिवहन और आवास से जुड़ी समस्याएं हावी रहीं।

डूसू चुनाव में बढ़ते नोटा के प्रयोग ने सभी संगठनों को चिंतित कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018 - 19 में कुल 27,581 मत सिर्फ नोटा पर हैं, नोटा के बढ़ते प्रयोग भविष्य में छात्र संगठनों के लिए घतरे की घंटी है। इस बार सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग सह सचिव पद पर 8,273 बार किया है, वहीं अध्यक्ष पद पर 6,211 तो उपाध्यक्ष पद पर 6,435 जबकि सचिव पद पर 6810 मत नोटा को मिले हैं। नोटा का प्रयोग वर्ष दर वर्ष बढ़ते जा रहा है। ■

उत्तराखंड के छात्रसंघ चुनाव में अभाविप का डंका

उत्तराखंड के महाविद्यालीन/विश्वविद्यालयीन छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने जीत का डंका बजाया है। इस बार उत्तराखंड के 73 महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव करवाया गया था जिसमें अकेले 218 प्रतिनिधि विद्यार्थी परिषद् से जीत कर आये हैं। देहरादून के प्रतिष्ठित डीएवी कॉलेज में लगातार बारहवें वर्ष जीत दर्ज कर अभाविप ने रिकार्ड स्थापित किया है। डीएवी कॉलेज में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जितेन्द्र बिष्ट ने एनएसयूआई के प्रत्याशी को 591 मतो के भारी अंतर से हराया है। वहीं देहरादून के डीबीएस पीजी कॉलेज में लगातार दूसरे साल भगवा परचम लहराया। जबकि मसूरी के एम बी पीजी कॉलेज में भी विद्यार्थी परिषद नें अध्यक्ष समेत चार पदों पर जीत दर्ज की।

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में भी सभी पदों पर अभाविप ने जीत दर्ज की है। ऋषिकेश ऑटोनोमस पीजी कॉलेज में 4 सीटों पर परिषद् ने जीत हासिल की। गैरसण महाविद्यालय में अभाविप के कमल सिंह रावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सूरज कुमार को हराया। उत्तरकाशी के पुरोला स्थित राजकीय महाविद्यालय में हुए छात्रसंघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद के प्रदीप रावत ने एनएसयूआई के विकास विश्वकर्मा को 22 वोट से हराया। अन्य पदों पर भी विद्यार्थी परिषद् के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कुमाऊँ मण्डल के प्रतिष्ठित एम बी पीजी कॉलेज हल्द्वानी में विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी गौरव कोरंगा अध्यक्ष पद पर विजयी रहे। पिथौरागढ़ और चंपावत में भी विद्यार्थी परिषद का दबदबा छाया रहा और अल्मोढा में भी विद्यार्थी परिषद ने जीत का परचम लहराया।

नैनीताल जिले की बात करें तो बेतालघाट महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में सभी पदों पर विद्यार्थी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गये। खटीमा महाविद्याल में अध्यक्ष पद पर परिषद् के प्रत्याशी ने एनएसयूआई के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। वहीं कपकोट और गरुड़ के महाविद्यालयों में भी अभाविप ने अध्यक्ष पद पर बाजी मारी। हल्द्वानी के प्रतिष्ठित इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर परिषद् की कार्यकर्ता दीपिका जोशी ने जीत हासिल की । गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर छात्र महासंघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सहित आठ पदों पर शानदार जीत दर्ज की। कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्र महासंघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सहित 5 पदों पर कब्जा किया। गुरुकुल कांगड़ी वि०वि० हरिद्वार में छात्र संघ चुनाव में राहुल शर्मा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। ■

राजस्थान के चार विश्वविद्यालयों में अभाविप का कब्जा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने राजस्थान के चार विश्वविद्यालयों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि एनएसयूआई सिर्फ जोधपुर और अलवर में जीत दर्ज कर सकी की। परिषद् जिन विश्वविद्यालयों में जीत हासिल की है उसमें महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, जगदगुरू रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, और अजमेर के एमडीएस विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं अगर महाविद्यालयीन छात्रसंघ चुनाव परिणाम की बात करें तो अधिकांश महाविद्यालयों में परिषद् समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है।

भरतपुर के महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर अभाविप के दिनेश भातरा ने जीत हासिल की है वहीं जयपुर स्थित जगदगुरू रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ में परिषद् के मुकेश उपाध्याय बने अध्यक्ष बने हैं जबकि उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हिमांशु बागड़ी की जीत हुई है, इसके साथ ही अजमेर के प्रसिद्ध एमडीएस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद् के लोकेश गोदारा ने विजय पताका लहराया है। राजस्थान के जयपुर, चितौड़ और कोटा प्रांत के अंतर्गत आने वाले अधिकांश महाविद्यालयों में परिषद् की जीत हुई है, हांलाकि राजस्थान विश्वविद्यालय में परिषद् को एक मात्र संयुक्त सचिव पर जीत मिली बाकी सभी पदों पर निर्दलीय जीते हैं। संयुक्त सचिव पद पर अभाविप की ओर से मीनल शर्मा ने 1469 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया है।■

दरकते कुनबे को बचाने की आखिरी कोशिश हिंसा

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अपने दरकते कुनबे को देखकर वामपंथी संगठन विचलित हो चुके हैं, यही कारण है कि अब वे हिंसा का सहारा ले रहे हैं। दरअसल जेएनयू छात्र संघ में साल - दर- साल जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के मत प्रतिशत में होती वृद्धि हो रही है, उससे वामपंथी संगठनों को घुटने के बल पर ला दिया है। यही कारण है जहां पिछले साल तीन वाम संगठन मिलकर छात्रसंघ चुनाव में लड़े थे, वहीं इस साल चारों वामसगंठनों को गठजोड़ कर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गठजोड़ के परिणामस्वरूप ये संख्यात्मक रूप से चुनाव तो जीत गये लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हार गये। क्योंकि चारों संगठनों के गठबंधन के बावजूद इस वर्ष भी जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में अभाविप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि अन्य विश्वविद्यालय की जेएनयू में भी उनका सूपड़ा साफ न हो जाए, जिस कारण अब वे हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। वामपंथी संगठनों के संघर्ष में परिषद् के कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है लेकिन अभाविप के कार्यकर्ताओं के हौसले आसमान पर है। जेएनएसयू के पूर्व संयुक्त सचिव और अभाविप कार्यकर्ता सौरभ शर्मा की मानें तो परिषद् मनोवैज्ञानिक रूप से यह चुनाव तभी जीत चुकी थी जब ये चार वामपंथी संगठन संयुक्त रूप से चुनाव में उतरे थे। उन्हें अब महसूस होने लगा है कि मुद्दों के बल पर तो जेएनयू में हम टिक नहीं सकते तो मतगणना की रात से ही आईसा एवं अन्य वामपंथी संगठनों के द्वारा परिषद् के कार्यकर्ताओं को डराया - धमकाया जाने लगा, उनकी धमकी से भी हमारे कार्यकर्ता नहीं डरे तो वे लोग हिंसा पर उतारू हो गये, विद्यार्थी परिषद् ने उनके हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया। उन्होंने बताया कि मतगणना पूरी होने और विजय हासिल करने के बाद उन्मादी वामपंथी भीड़ ने छात्रावास में गुंडागर्दी करते हुए घुमना शुरू कर दिया। पेरियार छात्रावास में रहने वाले परिषद् के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्दांत रूप से मारपीट की गई, जिसमें दिव्यांग कार्यकर्ता सुशील गंभीर रूप से घायल हो गये, इसी तरह सुजल को दौड़ा - दौड़ा कर पीटा गया उसके कपड़े फाड़े गये और उनके हाथ तोड़ दिये गये। अभाविप से जुड़ी कई छात्रा कार्यकर्त्ताओं के साथ हाथापाई की गई, उनके साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। ■

परिषद् की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गये हैं वामपंथी : निधि त्रिपाठी

अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री एवं जेएनयू की शोध छात्रा निधि त्रिपाठी का कहना है कि जेएनयू में परिषद् की बढ़ती लोकप्रियता से वामपंथी बौखला गये हैं, उन्हें यह आभास होने लगा है कि जल्द ही यहां से भी उनका बोरिया - बिस्तर समटाने वाला है। क्योंकि परिसर में उनलोगों ने छात्रों को बरगलाने के सिवा कुछ किया ही नहीं है। मतगणना और चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से वामपंथियों ने हिंसा का सराहा लिया, इससे उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। निधि ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि मतगणना के दिन से ही लगातार परिषद् के कार्यकर्ताओं एवं परिषद् के प्रति आस्था रखने वाले छात्रों के साथ ज्यादती की जा रही है। चुनाव के दूसरे दिन यानी 15 सितंबर को मतगणना के दिन दोपहर में परिषद् की अनुपस्थिति में मतपेटी खोले जाने का विरोध करते हुए परिषद् के 10 -15 कार्यकर्ता पुनः मतगणना की मांग कर रहे थे तो आईसा, एआईएफ समेत अन्य वामपंथी संगठन के करीब 200 - 250 लोगों के द्वारा परिषद् के कार्यकर्ताओं के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसमें सुफल नाम के एक कार्यकर्ता का हाथ टूट गया। छात्रा कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़कर उसका वीडियो बनाया, एक छात्रा के पैर पर बेंच पटकर मारा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद इनलोगों ने जमकर उत्पात मचाया, परिषद् के कार्यकर्ताओं को चुन - चुन कर लाठी और छड़ से मारा, एक छात्रा कार्यकर्ता जब पुलिस स्टेशन से लौट रही थी तो वामपंथियों ने दौड़ा - दौड़ा रॉड इत्यादि से मारा जिस कारण शरीर के कई हिस्से में में नीले निशान पड़े, इस दौरान उनलोगों के साथ कई बाहरी लोग भी शामिल थे। इतना कुछ करने के बाद भी कार्यकर्ताओं के हौसलों में कोई कमी नहीं आई है, यही परिषद् की सबसे बड़ी जीत है।

महात्मा गांधी की सार्धशती पर विशेष श्रृंखला-2

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में गांधी

। डा. जयप्रकाश सिंह ।

भारतीय इतिहास जिस दौर को 'गांधी-युग' कहता है, वह वैचारिक दृष्टि से रूमानियत और सम्मोहन का कालखंड है। उस समय कुछ संकल्पनाएं पूरी दुनिया को सम्मोहित किए हुए थीं। आम आदमी के बरक्स नेतृत्वकारी वर्ग पर इनका असर अधिक था। इसके कई कारण थे। आम आदमी के सामने यथार्थ की इतनी कठोर भूमि थी कि वह चाहकर भी विचारों की हवाई उड़ान अधिक समय के लिए नहीं भर सकता था लेकिन नेतृत्वकारी वर्ग के पास इसके लिए आवश्यक अवकाश और संसाधन थे। सम्मोहन का एक अन्य कारण यह भी था कि ऐसी संकल्पनाएं आधुनिकता और वैज्ञानिकता के कलेवर में परोसी गई थीं। ऐसे में उनको अपनाना, आगे बढ़ाना खुद को आधुनिक और वैज्ञानिक साबित करने के समान था और उनका विरोध करना खुद को पुरातनपंथी बताने जैसा था। पुरातनपंथी होने का खतरा कोई न तब उठाना चाहता था और न ही अब। आधुनिकता की संकल्पना को इस तरह गढ़ा गया था कि विचारों के सच का सरोकार हासिए पर पहुंच गया और परम्परा विरोधी होना ज्यादा महत्पवूर्ण हो गया था। इसके साथ ही ये संकल्पनाएं एकदम नई थीं, यथार्थ के धरातल पर इनका आकलन होना अभी बाकी था, कमियों का सामने आने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, चुनौती देने के धरातल तैयार नहीं हुए थे, इसलिए इन संकल्पनाओं में हर जगह अच्छाई का दर्शन होना स्वाभाविक था।

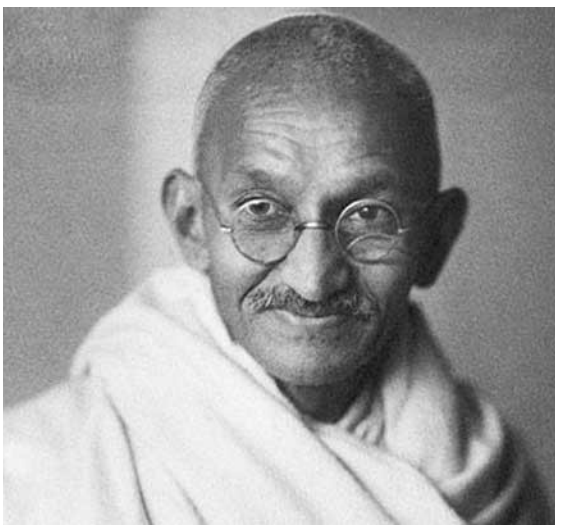

गांधी-युग की ऐसी ही सर्वाधिक-सम्मोहक संकल्पना थी-साम्यवाद और उससे सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीयतावाद का नारा। गांधी ने साम्यवाद को उसके हिंसक, अमानवीय और अप्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण सिरे से नकार ही, इससे भी बड़ी बात उनके द्वारा राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयतवाद की पूर्वशर्त के रुप में स्वीकार किया जाना था। गांधी राष्ट्रवाद को मानवता की बेहतरी के लिए एक आवश्यक उपकरण मानते थे। इसी कारण उन्होंने राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयतावाद की 'एंटी-थीसिस' मानने से इनकार कर दिया। वह मानते थे कि सच्चा राष्ट्रवादी ही अंतर्राष्ट्रीय चेतना के अधिक करीब पहुंच सकता है क्योंकि राष्ट्रवाद सामूहिकता की एक भावना पैदा करती है, जिसकी अंतिम परिणति अंतर्राष्ट्रीयतावाद के रूप में होती है। गांधी 18 जून 1925 को यंग इंडिया में लिखते हैं कि ' राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रवादी होना असंभव है। अंतर्राष्ट्रीयता तभी संभव है जब राष्ट्रवाद एक सच्चाई बन जाए।'

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांधी उन दृष्टिकोणों और तथ्यों से अनभिज्ञ थे, जिनके आधार पर उस समय राष्ट्रवाद की आलोचना की जा रही थी। वह जानते थे कि राष्ट्रवाद की यूरोपीय संकल्पना ने ही उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। वह यूरोपीय देशों के बीच चल रही गलाकाट प्रतिस्पर्धा और युद्धों का कारण भी उनके राष्ट्रवाद की संकल्पना में ढूंढते हैं लेकिन वह भारतीय राष्ट्रवाद को अलग मानते हैं। उनकी दृष्टि में भारतीय राष्ट्रवाद मात्र राजनीतिक नहीं है, वह सांस्कृतिक भी है। भारतीय राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक संदर्भों की तरफ

संकेत करते हुए 18 जून 1925 को यंग इंडिया में वह लिखते हैं कि 'राष्ट्रवाद बुराई नहीं है। आधुनिक राष्ट्रों की संकीर्णता, स्वार्थपरता और एकमेवता बुराई है। सभी दूसरों की कीमत पर लाभ कमाना चाहते हैं और दूसरे का विनाश कर अपना विकास करना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का रास्ता इससे पृथक है। भारत स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति और मानवता की सेवा के लिए स्वयं को संगठित करना चाहता है।'

वह राष्ट्रवाद को मानवता की सेवा उपकरण ठहराते हुए यंग इडिया के उपरोक्त अंक में लिखते हैं कि 'ईश्वर ने मुझे भारतीयों के बीच जन्म दिया है। यदि मैं उनकी सेवा नहीं करता तो अपने स्रष्टा के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। यदि मैं यह नहीं जानता कि उनकी सेवा कैसे की जा सकती है तो मुझे कभी भी इस बात का ज्ञान नहीं हो सकता कि मानवता की सेवा कैसे की जा सकती है।' इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वह हरिजन के 17 जनवरी 1933 के अंक में लिखते हैं कि 'सार्वजनिक जीवन में 50 वर्ष व्यतीत करने के बाद मैं मेरा इस सिद्धांत में विश्वास बढ़ गया है कि राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा में कोई असंगति नहीं है।

यंग इंडिया के 5 फरवरी 1925 के अंक में गांधी इस बात का पुनः संकेत देते हैं कि वह भारतीय राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मानते थे। वह लिखते हैं कि 'भारत मूलरूप से एक कर्मभूमि है भोगभूमि नहीं।' सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अपनी मान्यता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए वह 6 अप्रैल 1921 को यंग इंडिया में लिखते हैं कि- मेरी देशभक्ति मेरे धर्म के अधीन है। मैं भारत से वैसे ही सम्पृक्त हूं जैसे एक बच्चा अपनी मां के स्तनों से, क्योंकि मैं महसूस करता हूं इसने मुझे आध्यात्मिक पोषण प्रदान किया है। भारत ने मुझे वह परिवेश प्रदान किया है, जिसमें मेरी उच्चतम आकांक्षाएं अभिव्यक्त हो सकती है।'

गांधी का राष्ट्रवाद के प्रति यह दृष्टिकोण उस समय के राजनीतिक आख्यान के लिए एकदम नई परिघटना थी। गांधी ने राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक धरातल प्रदान कर इसके उदात्त स्वरूप को लोगों के सामने रखा। वह भारतीय राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बताकर उसे राजनीतिक विमर्श के केन्द्र में खड़ा कर देते हैं। सांस्कृतिक संदर्भों में राष्ट्रवाद को परिभाषित कर गांधी न केवल एक उदात्त भारतीय पहचान गढ़ते हैं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नया और व्यापक धरातल भी तैयार करते हैं।

उस समय जब अधिकांश नेता स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के वैश्विक मूल्य के आधार पर भारत को स्वतंत्र किए जाने का वकालत कर रहे थे, गांधी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उदात्त आधार पर भारत को स्वतंत्र किए जाने की मांग कर रहे थे। गांधी के अनुसार- 'मुझे अनुभूति होती है कि भारत की भूमिका अन्य देशों से पृथक है। भारत धार्मिक श्रेष्ठता के लिए सर्वाधिक योग्य है। इस देश ने स्वैच्छिक रूप से आत्मशुद्धि की जिस प्रक्रिया को आत्मसात किया है, उसकी दुनिया में कोई अन्य मिसाल नहीं मिलती।' (स्पीचेज एंड रायटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, पृष्ठ 405)

राष्ट्रवाद को राजनीतिक-आख्यान बनाकर, स्वतंत्रता आंदोलन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को केन्द्रीय विमर्श बनाकर गांधी ने भारतीय पहचान और भावधार की जो सेवा की है, उसका आकलन होना अभी बाकी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में गांधी का आकलन राष्ट्रवाद और गांधी दोनों के लिए जरूरी है। ■

(लेखक हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जनसंचार विषय के सहायक आचार्य हैं।)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का अक्टूबर 2018 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अभाविप ने निकाली 1,111 फीट की तिरंगा यात्रा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं की देशभक्ति अनोखी है, परिषद् के द्वारा निकाली गई यह तिरंगा यात्रा समाज को एक सूत्र में बांधकर उनमें राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए प्रेरणा का काम करेगी। उन्होंने कहा कि समाज के सभी तबकों को एकजूट कर एकत्रित करने की ताकत तिरंगे में हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है, विद्यार्थी परिषद् ने तिरंगा यात्रा निकालकर समाज को जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बधाई देता हूं।

वहीं अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से परिषद् ने समाज में देशभक्ति की एक लकीर खिंचने का काम किया है, जो युवाओं को राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए एक प्रेरणादायी कदम साबित होगी। यह राष्ट्र प्रेरणा पदयात्रा देशभर के सभी कार्यकर्ता एवं इकाई के लिए अनुकरणीय है।

प्रदेश मंत्री अभिजीत पटेल ने तिरंगा यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि यह तिरंगा पदयात्रा देश के शहीद जवानों एवं एशियन खेल में देश की मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा कि तैयारी 15 अगस्त से ही शुरू कर दी गई थी। अभाविप कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम में जाकर जरूरी समान का भेंट करना, साहित्य को बांटना, चर्मकार बांधव सत्कार, उत्कृष्ट सफाईकर्मियों का सम्मान, दिव्यांगों के साथ संवाद, रक्षाबंधन के दिन वृक्षों को राखी बांधकर पर्यावरण बचाने का संदेश किसानों के साथ संवाद, छात्रों के साथ संवाद इत्यादि के माध्यम से तिरंगा यात्रा के प्रति स्थानीय लोगों को जागृत किया। उन्होंने बताया कि अभाविप कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में तथा स्थानीय 77 महाविद्यालय में घुम - घुमकर तिरंगा यात्रा का प्रचार प्रसार शुरू किया। इस पूरे माह में 15 हजार पत्रक, तीन हजार पोस्टर शहर और महाविद्यालय में वितरित किये गये । इस दौरान तिरंगा यात्रा के लिए लगभग छः हजार छात्रों ने पंजीयन भी कराया।

तिरंगा यात्रा का उदघाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान एवं रा.स्व. संघ के प्रांत संघचालक मधुकर जाधव ने झंडा दिखाकर किया। तिरंगा का नेतृत्व एक छात्रा, भारत माता बनकर कर रही थीं। एक हजार एक सौ ग्यारह फीट की यह तिरंगा यात्रा सभी के लिए उत्सुकता का विषय था। यात्रा जिस गली से होकर गुजर रहा था, हर गली में स्थानीय लोग फूल बरसा कर कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे थे। उदघाटन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के हाथों सम्मानित किया। यात्रा का समापन शहर के क्रांति चौक में किया गया। ■

मिशन साहसी : 'निर्भर नहीं निडर'

|ममता यादव|

"फूल भी हैं चिंगारी भी हैं, हम भारत की नारी हैं", 'अबला नहीं तूफान हैं हम भारत की शान हैं', 'Next time you need help call yourself', बहुत छुपा है तुझमें साहस, उसको अब पहचान तुम, जाग उठों अब दुर्गा बनकर, इस राष्ट्र का सम्मान हो तुम।।' - ऐसे अनेकों नारों का आधार है मिशन साहसी.... अभाविप, विद्यार्थी निधि और मिशन प्रहार के संयुक्त तत्त्वाधान में जब मिशन साहसी के आयोजन का निर्णय हुआ तब एक उद्देश्य सबसे समक्ष था कि छात्राओं को 'निर्भर नहीं निडर' बनाना है। देश में आये दिन जिस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख मीडिया में होता है और समाज में जो अत्यंत चिंता का विषय बना हुआ है, वह है छात्रा सुरक्षा।

छात्राएं अपने पंखों को फैलाकर उड़ना चाह रही है। पायलट, सेना, डाक्टर, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, खिलाड़ी, पर्वातारोही, प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां छात्राओं ने अपने आपको सिद्ध ना किया हो। परंतु यह भी सत्य है कि कुछ विशेष कर पाना तभी संभव हो जब वह स्वयं को निडर महसूस कर सके। निडरता, आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण छात्रा जिस भी क्षेत्र में जायेंगी वहां अपनी कामयाबी के झंडे अवश्य गाड़ेगी। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद् प्रत्येक वर्ष देश भर में 'व्यक्तित्व विकास शिविर' के माध्यम से छात्राओं को आत्मसुरक्षा का प्रशिक्षण देती आई है। परंतु उनमें आनेवाली छात्राओं को यह अहसास हुआ कि हम तो कॉन्फिडेंट हो गये लेकिन देश में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली लाखों छात्राएं ऐसी हैं जो अभी भी स्वयं को निडर नहीं मानती है। अतः उन सबको भी निडर बनाना चाहिए और इसके मद्देनजर 'मिशन साहसी' की परिकल्पना की गई।

छः मार्च 2018 को मुंबई में लगभग दस हजार छात्राओं ने एक साथ आत्मसुरक्षा की टेक्निक्स का प्रदर्शन किया। मुंबई का बी.के.सी. ग्राउंड इस ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बना जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, अभिनेत्री रवीना टंडन, लीजेंड ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान और राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने छात्राओं में जोश भर देने वाले इस कार्यक्रम में भागीदारी की।

आगामी 30 अक्टूबर को पूरे भारत वर्ष में सभी प्रांतो के, सभी जिला केन्द्रों पर मिशन साहसी का आयोजन होने वाला है, जिसमें लगभग दस लाख से अधिक छात्राएं आत्मसुरक्षा की टेक्निक्स का प्रदर्शन एक ही दिन, एक ही समय, प्रातः नौ बजे से ग्यारह बजे तक करेंगी।

30 अक्टूबर को होने वाले इस विशाल प्रदर्शन की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न माध्यमों से लोग पूरे जोश के साथ इस आयोजन से जुड़ रहे हैं। क्योंकि अभाविप का मानना है कि अपराध होने के बाद उसके लिए न्याय मांगने के बजाय यदि अपराध होने ही न दिया जाये तो ज्यादा बेहतर है और मिशन साहसी का प्रयास है कि इसी सोच, इसी विचार को स्थापित करने का। जब छात्राएं निडर होगीं तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और निर्भर नहीं रहेंगी तो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी राह को चुन सकेंगी और राष्ट्र पुनर्निमार्ण में योगदान दे पायेगी। मिशन साहसी के

इस साहसिक आयोजन के साथ जुड़े और पढ़ेगी बेटी - बढ़ेगी बेटी के संकल्प को साकार करें।

आयोजन से जुड़े मुख्य बिंदु -

1. देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में यह प्रशिक्षण शिविर होंगे।
2. अधिकतम महाविद्यालय/विश्वविद्यालय और 10+2 विद्यालय तक पहुंचने का प्रयास
3. समाज की खेल व अन्य साहसी क्षेत्र से जुड़ी छात्राओं को ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में चयन
4. समाज की प्रबुद्ध महिलाओं का स्वागत समिति के माध्यम से सहभाग
5. प्रचार/प्रसार
6. 'निर्भर नहीं निडर' इस परिकल्पना को साकार करना
7. सभी स्थानों पर पोस्टर विमोचन, पत्रकार वार्ता और जनजागरण अभियान
8. विशेष दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली छात्राओं का प्रशिक्षण जो दिनांक 13 से 15 अक्टूबर तक संपन्न होगा।
9. पूरे भारत में एक ही समय, एक ही दिन, एक साथ आत्मसुरक्षा की टेक्निक्स का मात्र प्रदर्शन ही नहीं अपितु अपने जीवन का अंग बनाते हुए निर्भय और सम्मान के साथ जीन की कला का प्रत्यक्ष प्रदर्शन 30 अक्टूबर 2018 को प्रात 9 से 11 बजे होगा।

आइये इस नवरात्रि में नौ देवियों को अपना आदर्श मानते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। अपने साथ औरों को भी आत्मनिर्भर बनायें।

चले साहस की ओर, बने साहसी। मिशन साहसी।। ■

(लेखिका अभाविप की राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख हैं।)

अभाविप की मांगों के आगे झुका लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अवध प्रांत के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जबरन सेमेस्टर प्रणाली लागू करने, छात्रावास और मेस की कुव्यवस्था का सुधार न करने, छात्रों पर फर्जी मुकदमें लादने के विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, प्रारंभ में तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनकी मांगों को अनदेखा किया। प्रशासन की अनदेखी के बावजूद विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने भी हार नहीं मानी और क्रमबद्ध रूप से विरोध करने का निर्णय लिया। दो अक्टूबर को अभाविप के सैकड़ो कार्यकर्ता कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गये। कुलसचिव वार्ता करने आये लेकिन उनके मौखिक आश्वासन को परिषद् के कार्यकर्ताओं ने ठुकरा दी, ऐसे में कुलपति को कार्यालय छोड़कर जाना पड़ा। देर रात तक परिषद् के कार्यकर्ता कुलपति आवास के सामने डटें रहे और प्रदर्शन चलता रहा। कार्यकर्ताओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए अंततः विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा, उन्होंने परिषद् की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। कुलसचिव के आश्वासन के बाद आठ घंटे से चल रहा धरना अंततः देर रात को समाप्त हुई। अभाविप की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को दो सप्ताह का समय दिया गया है, अभाविप का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पुनः आंदोलन करने को विवश होंगे।

अभाविप के अवध प्रांत संगठन मंत्री धनश्याम शाही का कहना है कि आज प्रदेश के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ी समस्या सत्र की अनियमतता के कारण कक्षाओं का न चलना है। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिस्थितियों का संज्ञान लिये बिना विश्वविद्यालय द्वारा अपने निर्णय के माध्यम से सेमेस्टर सिस्टम थोपा जा रहा है। अभाविप ने लखनऊ विश्वविद्यालय को सुधार करने का मौका दिया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे में हमें आदोंलन के लिए उतरना पड़ा। वहीं अभाविप के प्रांत मंत्री राहुल कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात के अनुसार संसाधन नहीं है फिर भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर रहे हैं। इस व्यवस्था से शिक्षण संस्थाओं पर दबाब बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की और से मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा जिसका जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। ■

अभाविप के संघर्षों का परिणाम है, हरियाणा में छात्रसंघ चुनाव : विक्रांत खंडेलवाल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने कहा कि हरियाणा में 22 वर्षों के बाद छात्रसंघ चुनाव होने जा रहे हैं, यह चुनाव विद्यार्थी परिषद के साथ मिल कर छात्रों के द्वारा किये गये लम्बें संघर्ष का परिणाम है। हरियाणा में गत वर्षों में शासन करने वाले दल आज भले ही छात्रसंघ चुनावों की वकालत करें पर जब तक प्रदेश में इनके आकाओं की सरकारें रही तो इन्होंने एक भी दिन, एक भी बार कभी भी छात्रसंघ चुनावों की मांग नही की।

विद्यार्थी परिषद का प्रारंभ से ही मानना रहा है कि छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होना चाहिए। प्रदेश भर में परिषद द्वारा पिछले वर्षों में किया गया प्रत्येक आंदोलन प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की मांग के लिए था और है। हम सभी जानते है कि हरियाणा की राजनीति में परिवारों का बोलबाला है यहां आज तक भी सामान्य व्यक्ति बिना इन राजनीतिक मठाधीशों के आशीर्वाद के राजनीति में आने की सोच भी नहीं सकता है इन परिवारों ने ही विभिन्न पार्टियों में रह कर पूरे हरियाणा को लूटा है और हरियाणा से ज्यादा खुद का विकास किया है और इसी का परिणाम है कि यहां के बड़े नेता या तो जेल में है या फिर बेल में है आज हरियाणा के आम छात्रों में इन चुनावों ने एक उम्मीद जगाई है कि वो भी राजनीति में आकर देश समाज के लिए काम कर सकता है।

हरियाणा के छात्रसंघ चुनाव हरियाणा में युगपरिवर्तन करने वाले साबित होंगे

अभाविप, हरियाणा के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद से ही वर्षो से की गई तपस्या के फलस्वरूप मिले इस स्वर्णिम अवसर को छात्रहितों में पूर्ण सदुपयोग करते हुए प्रदेश भर के गांव, ढाणी के रहने वाले साधारण परिवारों के विद्यार्थियों को साथ लेकर प्रदेश भर में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, धनबल, भुजबल के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाई है। परिषद द्वारा चलाये जा रहे सतत आंदोलन की धार और तेज करते हुए परिषद् ने एक व्यापक योजना बनाते हुए वर्तमान कार्यकर्ताओं का जोश और परिषद के पूर्व कार्यकर्ताओं का संघर्ष और अनुभवों का भरपूर उपयोग करते हुए प्रदेश भर में आंदोलन का शंखनाद किया। सबसे पहले प्रान्त के छात्र नेताओं की रोहतक और करनाल में बैठक कर आंदोलन की रूप रेखा बनाई, मुद्दे निकाले और फिर 16 सितम्बर को प्रदेश भर के 1000 छात्रनेताओं का बड़ा सम्मेलन एमडीयू रोहतक में किया जिसमें परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर ने छात्र नेताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि छात्रहितों में परिषद द्वारा वर्षो से निरन्तर किया गया कार्य ही हमारी जीत का आधार बनेगा ! परिषद ने 22 सितम्बर को रोहतक में ही परिषद के

पूर्वकार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव बांटे और चुनावों में हर संभव सहयोग का वादा किया। पूर्व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिषद् के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत के कहा कि हरियाणा के विश्व विद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों के माध्यम से परिषद जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ने वालों की साजिश को नाकाम करेगी।

बताते चलें कि अभाविप हरियाणा ने "जीत से कम कुछ भी स्वीकार नही" का मंत्र लेकर हरियाणा के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनावों में जीत के लिए कमर कस ली है, उसी का परिणाम है कि क्लासरूम से लेकर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को जिला, नगर, महाविद्यालय स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए 24-25 सितम्बर को सभी जिला केंद्रों पर जिला सम्मेलन किये गये, जिनमें प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने सहभाग लिया। दरअसल कि परिषद् के द्वारा पहले हरियाणा में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ चुनावों की मांग , प्रदेश भर में सामान्य शिक्षा में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, सभी प्रकार की छात्रवृत्ति की राशि मे बढ़ोतरी, छात्रावासों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण , राज्य के शिक्षण संस्थानों में खेल सुविधाओं को विस्तार और प्रदेश भर की छात्राओं के लिए विशेष बसों की व्यवस्था आदि की मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन किया गया। इन मांगो को लेकर सम्पूर्ण हरियाणा के 250 से अधिक महाविद्यालयों , विश्वविद्यालयों के एक लाख छात्रों से संपर्क करने का महत्वपूर्ण अभियान चलाया और 28 सितम्बर को कुरुक्षेत्र, 4 अक्टूबर को हिसार , 5 अक्टूबर को रेवाड़ी में बड़ी रैलियां और 6 को एमडीयू रोहतक में छात्र प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया है जिनमें हरियाणा के सभी 22 जिलों के 20000 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में परिषद के कार्यकर्ता चुनाव लड़ें और जीतें इस लिए अब अन्तिम दौर की लड़ाई बाकी है जिसमें प्रदेश भर में चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण कक्षा प्रतिनिधि के लिए व्यक्ति का चयन, प्रमुख पदों के लिए व्यक्ति चयन आदि जरूरी कार्यो के लिए प्रदेश भर के प्रमुख कार्यकर्ता जुटेंगे और वर्षो के बाद हरियाणा में होने वाले छात्र संघ चुनाव में परिषद के राष्ट्रवाद और प्रदेश के आम छात्र को नेतृत्व को जीत दिलाएंगे। ■

महेन्द्रगढ़ सामूहिक दुष्कर्म घटना, सभ्य समाज पर कलंक : आशीष चौहान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में सीबीएसीई बोर्ड टॉपर तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना सभ्य समाज पर कलंक है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी कर उसे कठोर से कठोर सजा दे ताकि भविष्य कोई भी दुराचारी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखने के पहले हजार बार सोचे। उन्होंने कहा कि छात्रा सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा लिए गये कदम अपर्याप्त है, चौहान ने पुलिस कार्यवाही में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया।

वहीं अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री निधि त्रिपाठी ने देश को शर्मसार करने वाली इस घटना की भर्त्सना करते हुए कहा कि पहचान के लोगों द्वारा किया गया ये निंदनीय कृत्य समाज में संबंधों के गिरते स्तर को दर्शाता है। कानून के साथ - साथ समाज को भी इस मानसिकता के समूल नाश के लिए आगे आना होगा। अभाविप ने इस घटना को लेकर सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापना सौंपा है। सरकार ने भी दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। ■

राफ़ेल, राजनीति व राष्ट्र सुरक्षा

। राकेश यादव ।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका जब ईरान के साथ व्यापारिक मतभेदों के चलते तेल आयत ना करने का दबाव भारत पर डाल रहा है, मलेशिया की आड़ में चीन दक्षिण एशिया में भारत के विरोधियों को मजबूत करने पर तुला है। ऐसे में महज राजनीतिक जमीन की तलाश में राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ करने की प्रवृति से भारतीय राजनीतिक दलों को बाहर आने की जरूरत है। वो चाहे कश्मीर में अलगाववादियों की भारत विभाजन की नीति, ममता बनर्जी का बांग्लादेशियों को संरक्षण, रोहिंग्याओं की घुसपैठ का समर्थन या एनआरसी को लेकर विवाद। वैचारिक एवं राजनीतिक मतभेदों का ये अर्थ कतई नही हो सकता कि कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर की तरह भारत को मोदी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान की ओर ताका जाए। जम्मू में हाल ही में रोहिंग्या बस्ती की झुग्गी में मिले 30 लाख कैश इस दिशा में विचार को और अधिक मजबूत कर देते है। ऐसे समय में राफ़ेल डील का विवाद अपरिपक्व राजनीतिक समझ, कमजोर विपक्ष, गैर लोकतांत्रिक कृत्य, राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ व रक्षा क्षेत्र में भारत की बढती ताकत को रोकने के अलावा कुछ नही हो सकता।

ये प्रवृति केवल बयानबाजी तक ही सीमित ना रहकर 21 जुलाई, 2018 को भारतीय लोकतंत्र के साथ विपक्ष द्वारा किए गये सबसे बड़े तथ्यहीन, निराधार संवैधानिक मजाक अविश्वास प्रस्ताव के रूप में संसद तक भी पहुंच गयी। अविश्वास प्रस्ताव के दिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में राफ़ेल फाइटर जेट की डील के मुद्दे को उठाते हुए कह डाला कि राफ़ेल विमानों की कीमतों को लेकर उनकी चर्चा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रों से हुई। और इतिहास में यह पहली बार हुआ, जब भारतीय संसद में बहस चल रही हो और किसी विदेशी सरकार को उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। फ्रांस राष्ट्रपति कार्यालय ने तत्काल प्रभाव से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि - "राफ़ेल डील को लेकर उनकी राहुल गांधी से कोई बात नही हुई है। ये डील भारत व फ्रांस के आर्थिक, औद्योगिक एवं रणनीति हितों को ध्यान में रखकर की गयी है।"

राफ़ेल विवाद फिर से 1989 में हुए बोफोर्स घोटाले की याद दिला रहा है। कांग्रेस लगातार राफ़ेल को लेकर मुखर हो रही है। राफ़ेल के बहाने राहुल गांधी उनके पिता राजीव गांधी की सरकार गिराने वाले भ्रष्टाचार के कलंक का बदला लेना चाहते है। साथ ही, 2019 के चुनाव के लिए मुद्दा भी खड़ा करना चाहते है। राफ़ेल डील विवाद वर्तमान मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने वाला सौदा साबित हो रहा है। नियमित रूप से नये-नये आरोप लगाकर जनता में उस मुद्दे को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है जिसमें की विपक्ष नाकामी साफ़ झलक रही है।

राफ़ेल जेट डील की शुरुआत उस समय हुई जब भारत को सुरक्षा के मोर्चे पर चीन से सीमा पर तनातनी, पाकिस्तान सीमा पर नियमित विवाद जैसे तमाम पड़ोसी देशों से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रस्ताव रखा। यह डील कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग प्रथम सरकार में परवान चढ़ी। संप्रग सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटोनी की अगुवाई वाली रक्षा खरीद परिषद ने अगस्त 2007 में 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी। लड़ाकू विमानों की रेस में अमेरिका के बोइंग एफ/ए-18ई/एफ सुपर हॉरनेट, फ्रांस का डसॉल्टल राफेल, ब्रिटेन का यूरोफाइटर, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन एफ-16 फाल्क न, रूस का मिखोयान मिग-35 और स्वीडन के साब जैस 39 ग्रिपेन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल थे। परन्तु राफेल को लेकर सहमति बनी क्योकिं राफेल की कीमत दौड़ में शामिल बाकी जेट्स की तुलना में काफी कम थी और इसका रख-रखाव भी काफी सस्ता थि। दूसरी तरफ, ये 3 हजार 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यही वजह थी कि डील राफेल के पाले में गई। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने कई विमानों का तकनीकी परीक्षण और जांच किया और यह प्रक्रिया 2011 तक चलती रही। वायुसेना ने जांच-

परख के बाद 2011 में राफेल को अपने पैरामीटर पर खरा पाया। 2012 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली संप्रग द्वितीय में राफेल को बिडर घोषित किया गया और इसके उत्पादन के लिए डसाल्ट एवीएशन के साथ बातचीत शुरू हुई। उस समय एक राफ़ेल की कीमत 1705 करोड़ तय की गयी थी. सरकारी तंत्र की नाकामी एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते बातचीत 2014 तक यह खरीद प्रक्रिया किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। भारत के लिए अत्यंत जरुरी इस रक्षा सौदे को 2007 से 2014 तक नही कर पाना सरकार की मंद राजनीतिक शक्ति, सैन्य मामलों में सरकारी निष्क्रियता के साथ-साथ कमीशनखोरी की निशानी से सिवाय कुछ नही सकती। आज बडा सवाल है की रक्षा डील को रोकने का भरकस प्रयास कर रही कांग्रेस, 10 सालों में इस डील को क्यों नही कर पायी ?

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही रक्षा क्षेत्र व सुरक्षा तन्त्र की मजबूती पर विशेष बल के चलते राफेल जेट की डील में सुगबुगाहट तेज हुई। प्रधानमंत्री इस विमान सौदे के जरिये आधुनिक हथियार खरीद व मेक इन इंडिया दोनों उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा के चलते 2015 में पीएम मोदी फ्रांस गए और उसी दौरान 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर समझौता किया गया। इस समझौते में यह बात भी थी कि भारतीय वायु सेना को उसकी जरूरतों के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर विमान मिलेंगे तथा विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी फ्रांस की होगी। भारत ने राफ़ेल निर्माता फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन को कई बड़े बदलाव के लिए कहा जिसके बाद कंपनी ने 10 नये अपग्रेड भी किए है। आखिरकार सुरक्षा मामलों की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दोनों देशों के बीच 2016 में आईजीए हुआ। भारत-फ्रांस के बीच समझौता होने के करीब 18 महीने के भीतर विमानों की आपूर्ति शुरू होने की बात थी। लेकिन 'राफेल डील' को लेकर कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ये डील केवल जुबानी जंग बनकर रह गईं, जबकि संप्रग की तुलना में मोदी सरकार ने ये सौदा प्रति विमान 67 करोड़ रूपये सस्ते में किया है। मोदी सरकार की राफ़ेल डील की पारदर्शिता व प्रतिबद्धता का पता 2 सितम्बर को लगा जब 3 राफ़ेल विमान ग्वालियर के महाराजपुर एयरबेस पर उतरे और भारतीय वायुसेना के पायलटों को राफ़ेल का प्रशिक्षण दिया गया।

फ्रांस से रक्षा सौदे को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिस तरह संसद को गुमराह किया वो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदराना हरकत व देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। विदेशी एवं अस्त्र संबंधो को लेकर सुरक्षा एवं गोपनीयता के करार का उल्लंघन राष्ट्र हित में भी नहीं हो सकता। संप्रग सरकार के दौरान आठ वर्ष तक रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी ने अनेक अवसरों पर रक्षा मामलों से जुड़ सवालों का संसद में राष्ट्रहित से जुड़ मामले बताकर जवाब नहीं दिया था। आज जब राफेल की जो कीमत पिछली सरकार के समय तय की गई कीमत से नौ फीसदी यानी करीब 67 करोड़ रुपए कम है और मौजूदा सौदे की सेवा शर्तें भी बेहतर हैं, ऐसे में विपक्ष के सवाल एवं रैलियों का विषय बनाना महज राजनीतिक ही है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर की रैली में आरोप लगाया कि राफ़ेल डील में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दरकिनार किया गया। कुछ समय बाद ही रिलायंस ने राहुल के भाषण का खंडन करते हुए कहा कि रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट रक्षा मंत्रालय की बजाय डसॉल्ट से मिला है, जो की सच्चाई भी है। 36 राफेल फाइटर जेट्स सप्लाई करने वाली कंपनी डसॉल्ट ने रिलायंस डिफेन्स को 'ऑफसेट' या एक्सपोर्ट काम के लिए चुना है। अथार्त विदेशी वेंडर के लिए भारतीय पार्टनर चुनने में रक्षा मंत्रालय व भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है।

रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश धींगरा ने भी इस मुद्दे पर कहा कि - "दो सरकारों की बीच हुई डील के मुताबिक सभी 36 एयरक्राफ्ट्स की आपूर्ति 'फ्लाई-वे' कंडीशन में होनी है। इसका मतलब यह है कि उन्हें फ्रांस से डसॉल्ट के द्वारा निर्यात किया जाएगा इसलिए एयरक्राफ्ट का प्रॉडक्शन भारत में होना ही नही है तो 'HAL' या अन्य कोई भी प्रॉडक्शन एजेंसी से निर्माण का सवाल ही नहीं हो सकता।'' सवालों का औचित्य उसकी सच्चाई में ही रहता है और उससे भी ज्यादा उसकी मंशा उसकी सार्थकता को सिद्ध करती है। आज कांग्रेस अध्यक्ष के सवालों में राष्ट्र सुरक्षा, सेना सम्मान, विदेशी संबंधों को दरकिनार कर महज राजनीति करना उनकी इसी मंशा को दर्शा रहा है। राजीव गांधी के बफोर्स व दस साल के शासन में लगे भ्रष्टाचार के कलंक केवल आरोपों से नही धुल सकते। ■

MAHARAJA HARI SINGH THWARTED BRITISH CONSPIRACY: ACCEDED J&K TO INDIA

India became independent on August 15, 1947, and it was divided into two nations on August 14. This was the result of Congress accepting the two- nation theory of Muslim League.

On the demand of Muslim League, a new state emerged in the name of Pakistan and its leader Mohammed Ali Jinnah was made its first Governor General. Pandit Jawahar Lal Nehru, after becoming the Prime Minister of India, addressed the nation, calling it our 'Tryst with Destiny'. The last British Governor General and the key person behind the Partition Lord Mount Baton continued to be in his post even after Independence on the request of Congress.

The Partition of India was not an indispensable and compulsory result of the contemporary situation. It was a part of the British policy, which every Indian understood. The special provisions for Muslims in the Government of India Act 1935 had given clear indication that the British were strengthening the grounds of Partition on communal lines. Addressing the Haripura Convention as Congress President in 1938, Subhash Chandra Bose had said, "The British separated Alstar from Ireland, in Philistine they will separate the Jews from the Arabs. Even after giving the power it is necessary to divide in order to make the two parts weak." In the Indian Constitution the same policy of division is present in a different form."

These seeds of Partition were present in the Government of India Act 1935. In order to implement their strategy the British wanted the shoulder of an Indian, and this requirement was fulfilled by Mohammed Ali Jinnah. All the efforts of Chakravorty Rajgopalachari for Hindu-Muslim unity during 1943-44 had failed. His proposals forwarded to Jinnah were somewhat similar to accepting the demands of Pakistan, which was indirectly approved by Mahatma Gandhi also. Their expectation from Jinnah was this much that this agreement should be implemented only when the Britain handed over the self-rule rights to India. They also wanted that both parties should struggle together for ensuring

21st April 1944: Sir Hari Singh Bahadur, the Maharajah of Jammu & Kashmir and one of India's two representatives at the British War Cabinet inspects civil defence workers in Bermondsey, London.

that these rights are transferred at the earliest. But Jinnah declined this proposal. Jinnah was also prepared that Pakistan should be formed while the British are in India and he should be made the Supreme Head of this new country. After that the British leave India or not is immaterial.

The British Government brought the Muslim League in forefront in order to execute their conspiracy. They did not even think it necessary to do it behind the curtain. The then Viceroy Lord Wavell accepted in front of Mahatma Gandhi on an occasion that their sympathy was with the Muslim League. On March 23, 1946, the Cabinet Mission reached India. Its members tried to understand the situation by talking to different organizations and individuals. The result was that there was no possibility of compromise between the Congress and Muslim League. Congress was of the opinion that British should leave India by transferring power to whosoever they want, and the Indians will take a decision for themselves. But this opinion was not acceptable to the Cabinet Mission.

On April 27, 1946 the Cabinet Mission suggested that in India there should be a Central Rule in order to control foreign affairs, defence and communication. Further, it said that two groups should be formed of the provinces – one of the Hindu-dominated provinces and other of the Muslim-dominated provinces. Even before this proposal could be discussed in Congress Working Committee, Maulana Azad sent a personal massage to Cabinet Mission, accepting the proposal and that he will convince the Congress working committee for it. However it was another matter that the Congress working committee, under pressure of the nationalist leaders, expressed disagreement with the proposal.

India's population was 39 crore as per the census of 1941, in which the population of Muslim-dominated provinces was even less than 10 crore. On the basis of available data, British and Jinnah both considered Bengal and Assam as Muslim-dominated, where the Muslim population was 51.69%. Similarly, the non-Muslim population in Punjab, frontier provinces, Sindh and Baluchistan was 37.93%. The British were eager for making separate nation for 23% Muslims, whose the only representative was Jinnah, and they did not care for the opinion of 76.19% Hindus. They had no policy for Hindus living in Muslim-dominated areas, even though the Hindu population there was only a little less than 50%. The Congress had reservations on this proposal but the Muslim League declared that they accepted the proposal. That is why the Congress had to decide in favour of joining the Interim Government.

For this, a meeting of the Presidents of both the organizations was organized with the Viceroy. Maulana Azad was then President of Congress. Jinnah refused to sit with Azad because according to his philosophy, the Hindus were only enemy, but the Muslims who oppose Muslim League is treacherous and therefore he cannot sit with such a person. Congress yielded and sent Nehru in place of Maulana Azad but even then Jinnah did not turn up. The elections for Constituent Assembly were held in 1946. Total 205 seats out of 292 were bagged by the Congress. Muslim League wan 73 seats out of 78 seats reserved for Muslims. Congress won 199 seats out of 210 seats which were unreserved. The elected representatives of Muslim League boycotted the Constituent Assembly.

According to Mountbatten plan, the provisions of Constituent Assembly were not to be implemented in the parts of the country, which were not ready to accept it. For knowing the opinion of these parts, it was proposed that the Legislative Assemblies of Bengal and Punjab should have their meetings in two parts. The first part should cover the Muslim-dominated districts and the second part should cover the other areas. Each Legislative Assembly member should decide about Partition through separate voting. If in a particular part, the members decide in favor of Partition with simple majority then the Partition will be accepted.

The Legislative Assembly of Sindh

was also given the similar right of self-determination. Since there was a Muslim League government there, the decision was pre-determined. In the frontier province and Muslim-dominated district Silahat of Assam, it was announced that the decision will be taken through referendum. It may be mentioned here that since there was a Muslim League government in Sindh, therefore the Constituent Assembly of that province gave it the right of self-determination. In Frontier Province there was a Congress government, but it was announced for it that the decision will be taken through referendum. Similarly, the Muslim-dominated Silahat district also was given a chance to referendum. But the Hindu-dominated Tharparker district of Sindh was not given the same opportunity. The Congress Working Committee, which was eager for Independence, instead of opposing this injustice, preferred to get freedom from the obstinacy of Muslim League at any cost. In the Congress Working Committee only Khan Abdul Gaffar Khan opposed the Partition but he was not supported by any big leader including the President Maulana Azad.

In the Frontier Province even before referendum the Muslim League workers started attacking the Hindus. Not getting any protection from the administration, they had to flee from the Frontier Province. Even the Non-Muslim League Muslims were threatened of dire consequences, if they voted against Partition. It was said that this referendum was between the Kafirs and Islam.

Khan Abdul Gaffar Khan demanded that if Muslim League wants a separate nation for itself then the Pathans should also get Pakhtunistan. It was neither acceptable to the British nor to the Muslim League. But here they committed a great political blunder. Khan Abdul Gaffar Khan, the unanimous leader of Pakhtuns, and his followers 'Khudai Khidmatgar' and Congress boycotted the referendum. As a result, Muslim League won by a slender majority and the Frontier Province was merged with Pakistan. Had the referendum not been boycotted, then certainly the Frontier Province would have been a part of India. In this situation the Geography and History would have been different. And this is also certain that the problem arising with Jammu & Kashmir would have not taken roots.

In this background when almost all the parties were mentally prepared for Partition, the Partition was inevitable. But all others, except Muslim League, were expecting that once the immediate frenzy gets over, the Partition and its demand will become irrelevant. The British also had this in mind and therefore they considered it necessary that some controversial issues must remain unsettled so that the hostility between both the countries may continue. This possibility existed in Jammu & Kashmir and therefore they not only made it controversial but also contributed to make this dispute more complex.

Jammu & Kashmir was the largest princely state of India. Both India and Pakistan wanted to annex it with them because this was on the borders of both the countries. But as per the provisions of the Independence India Act of India, 1947, Maharaja Hari Singh was the only authority to take a decision on whether to accede Jammu & Kashmir with India or with Pakistan. It has already been said earlier that Jinnah was pressurizing the Maharaja to accede his state with Pakistan, while Mahatma Gandhi had advised him to act in accordance with the aspirations of the people. On the other hand, Governor General Mountbatten had assured the Maharaja that if he decided to merge with Pakistan, India would not object. Lord Mountbatten and Lord Isme urged the Maharaja to take an immediate decision in favour of Pakistan and told him that the Congress will not have any objection. Despite all this the Maharaja Hari Singh decided to merge Jammu & Kashmir with India, and not with Pakistan. ■

[This article is an extract from the book "Jammu Kashmir: An Analysis of Facts" authored by Sh. Ashutosh. Further chapters of this book will be covered later in a series.]

आन्दोलन

पं बंगाल के दिनाजपुर के दारवीट क्षेत्र के विद्यालय में दो छात्रों की हत्या का निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सिलिगुड़ी में धरना पर बैठे रा. संगठन मंत्री सुनील आंबेकर व अन्य कार्यकर्ता

पं. बंगाल में छात्रों की हत्या के विरूद्ध हैदराबाद में अपने आंखों में पट्टी बांधकर विरोध करते अभाविप कार्यकर्ता

छात्रों की हत्या के खिलाफ ममता सरकार के विरूद्ध कानपुर में नारा लगाते अभाविप कार्यकर्ता

पं. बंगाल में छात्रों की हत्या के विरूद्ध दिल्ली में सड़क पर उतरे अभाविप कार्यकर्ता, साथ में हैं अभाविप के रा. सह संगठन मंत्री श्रीनिवास

भोपाल में दोनों छात्रों को श्रद्धांजली देते अभाविप के रा. सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत व अन्य अभाविप कार्यकर्ता

रांची में ममता बनर्जी की पुतला दहन करते अभाविप कार्यकर्ता

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 October, 2018
Date of Publishing: 8 October, 2018

दावे नहीं प्रमाण

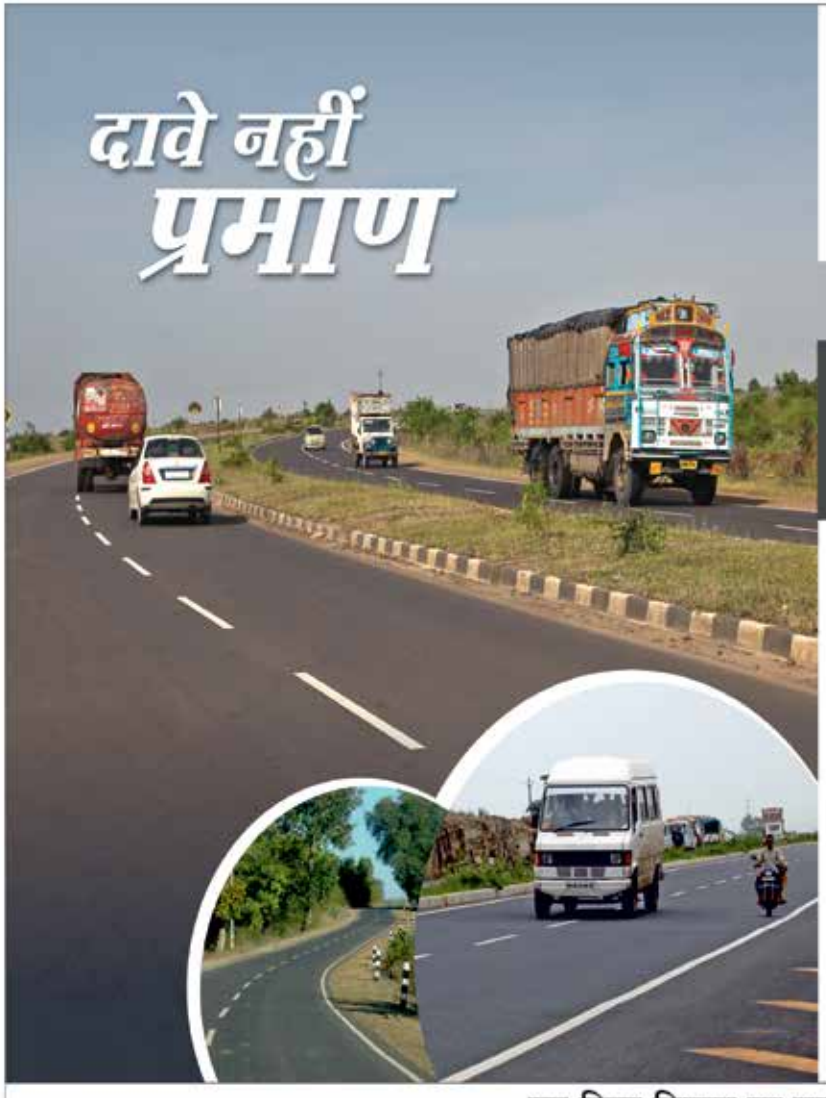

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

सड़क निर्माण में क्रांतिकारी कदम उठाए प्रदेश के विकास में गति लाए

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 से लेकर 2018 तक शहरों ही नहीं, गांवों में भी सड़कों का निर्माण किया है जिससे आवागमन सुगम हो गया है।

पूरा किया विकास का वादा, आगे है अटल इरादा